▪ RNI No. : TNHIN/2013/5252 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 204 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 20-02-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 भारत में इसी साल शुरू हो जाएगा दुर्लभ स्थायी चुंबक का उत्पादन : किशन रेड्डी

6 रोबोडॉग से परे : भारतीय उच्च शिक्षा का खोखलापन

7 सनी लियोनी के दिल में 'कैनेडी' को लेकर बैठा डर

फर्स्ट टेक

नाइजीरिया में खदान में जहरीली गैस के रिसाव से 37 लोगों की मौत

अबुजा/एपी। उत्तर-मध्य नाइजीरिया में एक खदान में जहरीली गैस के रिसाव से 37 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता अल्फ्रेड अलाबो ने एक बयान में कहा कि घटना मंगलवार तड़के पठार राज्य के वासे क्षेत्र में स्थित कम्पानी जुरक समुदाय में हुई। उन्होंने कहा, ''प्रारंभिक जांच से पता चला है कि खनिक लेड ऑक्साइड तथा सल्फर एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी अन्य संबंधित गैसों के अचानक रिसाव के कारण प्रभावित हुए थे, जो मनुष्यों के लिए विषाक्त और जहरीली होती हैं, खासकर एक बंद या खराब हवादार वातावरण में इन गैसों का असर खतरनाक होता है।''

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति 'मार्शल लॉ' लागू करने के दोषी करार

सियोल/एपी। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को दिसंबर 2024 में 'मार्शल लॉ' लागू करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जी कुई-यून ने कहा कि उन्होंने यून को 'नेशनल असेंबली' (संसद) पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास के तहत सेना और पुलिस बल को जुटाने, नेताओं को गिरफ्तार करने और ''कुछ समय'' तक निरंकुश शासन स्थापित करने का दोषी करार दिया। नेशनल असेंबली में विपक्षी उदारवादी सांसदों का बहुमत है। यून के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की संभावना है। एक विशेष अभियोजक ने यून के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि उनके कार्यों ने देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया और वह सबसे गंभीर सजा के हकदार हैं।

मानव मस्तिष्क अभी भी सर्वोपरि : नारायण मूर्ति

नई दिल्ली/बेंगलूरु। इंफोसिस के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति ने बुधवार को संकेत दिया कि बार-बार किए जाने वाले दावों के बावजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शायद कभी मानव मस्तिष्क की जगह नहीं ले पाएगी। नारायणमूर्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में कहा, मानव मस्तिष्क से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आधिकारिक बयान के अनुसार, 'लीडर्स टॉक' नामक यह संवाद 'स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप' (एसओयूएल) के सहयोग से वाइसरीगल लॉज सभागार में आयोजित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, मूर्ति ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को खतरे के बजाय वरदान बताया और युवाओं के लिए कौशल विकास व सीखने की क्षमता के महत्व पर जोर दिया।

भारत को एआई में भविष्य की संभावनाएं नजर आती हैं : मोदी

प्रधानमंत्री ने एआई के लिए 'मानव विजन' का अनावरण किया, प्रौद्योगिकी पर मानव नियंत्रण की वकालत की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की पहुंच सभी तक सुनिश्चित किए जाने की वकालत करते हुए बृहस्पतिवार को 'मानव विजन' का अनावरण किया जिसके तहत संप्रभुता और समावेशिता पर विशेष जोर देते हुए तेजी से उभरती इस प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री ने यहां 'एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दुनिया की भलाई के लिए वास्तव में तभी काम आएगी जब इसे साझा किया जाएगा और इसके कोड सार्वजनिक होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश एआई से डरता नहीं है बल्कि इसमें भविष्य की संभावनाएं देखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी का कल्याण और खुशहाली एआई के लिए ''हमारा मापदंड'' है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मनुष्य महज 'डेटा' बिंदु या कच्चा माल न बनकर रह जाए।

मोदी ने कहा, ''मैं एआई के लिए 'मानव' (एमएएनएवी) दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हूं जिसमें 'एम' का अर्थ 'मोरल एंड इथिकल सिस्टम्स' (नैतिक एवं नीतिपरक प्रणालियां), 'ए' से तात्पर्य 'अकाउंटेबल गर्वनेंस' (जवाबदेह शासन), 'एन' से तात्पर्य 'नेशनल सॉवेरिनिटी' (राष्ट्रीय संप्रभुता), 'ए' से तात्पर्य 'एक्सेसबल इंड इन्क्लूसिव' (सुलभ और समावेशी) और 'वी' से तात्पर्य 'वैलिड एंड लेजिटिमेट' (वैध और कानूनी) है।''

इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पॉहमेलॉ सहित दुनिया भर के नेता और कई प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उपस्थित थे।

मोदी ने कहा कि भारत का 'मानव' दृष्टिकोण 21वीं सदी की एआई-संचालित दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

मोदी ने कहा, ''हमें एआई को खुला आकाश देना है, लेकिन

एआई का लोकतंत्रीकरण ही आगे बढ़ने का उचित एवं सुरक्षित रास्ता : ओपनएआई सीईओ

नई दिल्ली/भाषा। ओपनएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सैम ऑल्टमैन ने बृहस्पतिवार कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) का लोकतंत्रीकरण ही आगे बढ़ने का एकमात्र उचित एवं सुरक्षित मार्ग है। 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' 2026 में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एआई को व्यवहार में उतारने के अपने मिशन में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 'ट्रू सुपर इंटेलिजेंस' के शुरुआती संस्करण कुछ ही वर्षों में सामने आ सकते हैं।'' उन्होंने कहा, इस संभावना की तैयारी करते समय हम तीन मूल मान्यताओं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। पहला, हमारा मानना है कि एआई का लोकतंत्रीकरण ही आगे बढ़ने का एकमात्र उचित और सुरक्षित रास्ता है। एआई का लोकतंत्रीकरण यह सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले

द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल डीएमडीके

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले, दिवंगत अभिनेता विजयकांत की पार्टी डीएमडीके राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव एलायंस' में बृहस्पतिवार को शामिल हो गई, जिससे हफ्तों से जारी अटकलों पर विराम लग गया है। डीएमडीके के गठबंधन में शामिल होने संबंधी समझौते को यहां अन्ना अरिवालयम में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की मौजूदगी में अंतिम रूप दिया गया। डीएमडीके महासचिव प्रेमलता विजयकांत ने यहां स्टालिन से मुलाकात कर इस समझौते को अंतिम रूप दिया। इस दौरान प्रेमलता के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें कोषाध्यक्ष एल के सुधीश भी शामिल थे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कैप्टन विजयकांत द्वारा स्थापित पार्टी डीएमडीके गठबंधन में शामिल हुई है।''

स्टालिन ने कहा, ''मैं प्रेमलता विजयकांत का उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। वह बेहद कुशलतापूर्वक पार्टी का संचालन कर रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''उम्मीद है कि गठबंधन तमिलनाडु की प्रगति और समृद्धि में लगातार योगदान देता रहेगा।'' उन्होंने ''द्रविड़ मॉडल'' के शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर जोर दिया।

बाद में, द्रमुक पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, प्रेमलता ने कहा, कैप्टन (विजयकांत) और कलैगनार (के करुणानिधि) के आशीर्वाद से, हमने द्रमुक के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने कहा, ''जल्द ही सीट बंटवारे के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा।'' लोकसभा के लिए 2024 में हुए चुनाव में डीएमडीके अन्नाद्रमुक गठबंधन का हिस्सा था।

नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है : सीआरपीएफ महानिदेशक

गुवाहाटी/भाषा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक जी.पी. सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मार्च तक देश से इस खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

उन्होंने यहां बल की डीजी परेड को संबोधित करते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने पिछले साल अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियानों में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं। महानिदेशक ने कहा, ''नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है, उसी के अनुसार मार्च 2026 तक यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।''

सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान मणिपुर में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हमारा बल एक निष्पक्ष एजेंसी के रूप में इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतने में सक्षम रहा है।'' सीआरपीएफ की वर्षगांठ परेड से पहले डीजी परेड आयोजित की गई।

शनिवार को वर्षगांठ परेड में अमित शाह शामिल होंगे।

डीजीजीआई ने 13,000 करोड़ रुपए के अवैध ऑनलाइन गेम गिरोह का भंडाफोड़ किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) की हैदराबाद इकाई ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने संबद्ध वित्तीय-प्रौद्योगिकी कंपनियों की मदद से देश में अवैध ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट संचालित कर रहे एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। डीजीजीआई ने बताया कि उसने ऑनलाइन गेमिंग गिरोह के खिलाफ सघन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत संबद्ध वित्तीय-प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है, बैंक खातों में करीब 100 करोड़ रुपये के लेन-देन पर रोक लगा दी गई है और सरगनाओं की गिरफ्तारी की गई है।

डीजीजीआई की हैदराबाद इकाई द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग जांच के तहत उसने शहर की कंपनी 'एडसम एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड' के संस्थापक एवं निदेशक पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। यह कंपनी धोखाधड़ी पकड़ने और ग्राहकों की पहचान/डिजिटल केवाईसी सत्यापन की सेवाएं देती है। इसमें कहा गया, ''जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला कि 13,000 करोड़ रुपये का एक संगठित गिरोह अवैध ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट संचालित कर रहा था।

भाजपा ने कर्नाटक में 2028 में सत्ता में वापसी का संकल्प लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और 2028 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की सत्ता में वापसी का विश्वास जताया।

कर्नाटक में विपक्षी पार्टी ने यहां पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित अपनी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में चार प्रस्ताव भी पारित किए। इनमें राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी निधियों का दुरुपयोग, मादक पदार्थ से जुड़ा बढ़ता खतरा, कृषि समस्या और बेंगलूरु में कचरा संकट जैसे मुद्दे शामिल हैं।

पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी राम जी) लागू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। कार्यकारी समिति ने 'वंदे मातरम्' गीत को सम्मान देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने राज्य में 'शून्य विकास' का आरोप लगाया और सत्ताधारी पार्टी के भीतर मतभेद का दावा किया।

ट्रंप ने गाजा पर 'शांति बोर्ड' का अनावरण किया

वाशिंगटन/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को गाजा के लिए प्रस्तावित 'शांति बोर्ड' का अनावरण किया। इस दौरान नौ सदस्य देशों ने गाजा राहत पैकेज के लिए सात अरब अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जताई जबकि पांच देशों ने युद्धग्रस्त फलस्तीनी क्षेत्र में तैनात किए जाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय बल में भाग लेने के लिए सैनिकों को भेजने पर रजामंदी जताई। इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया ने 'गाजा स्थिरीकरण बल' के लिए सैनिक भेजने का वादा किया है, जबकि मिस्र और जॉर्डन ने इन प्रयासों के लिए पुलिस को प्रशिक्षित करने की प्रतिबद्धता जताई है। योजना के तहत सबसे पहले सैनिकों को राफा में तैनात किया जाएगा, जो एक प्रमुख केंद्र है। अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद है कि वह सबसे पहले पुनर्निर्माण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस बीच, ट्रंप ने कहा कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और कुवैत ऐसे देश हैं जिन्होंने संकल्प लिया है। ट्रंप ने अंशदान करने वाले देशों को धन्यवाद देते हुए कहा, ''खर्च किया गया हर डॉलर स्थिरता और एक नए एवं सौहार्दपूर्ण क्षेत्र की आशा में निवेश है।''

गगनयान 'ड्रोग पैराशूट' के लिए डीआरडीओ ने मुख्य परीक्षण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा किए गए परीक्षण ने उच्च क्षमता वाले 'रिबन पैराशूट' के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता को साबित किया है। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह परीक्षण 18 फरवरी को चंडीगढ़ में 'टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी (टीबीआरएल) में डीआरडीओ के 'रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड' (आरटीआरएस) प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया।

इसमें कहा गया, ''भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने गगनयान कार्यक्रम के लिए 'ड्रोग पैराशूट' के सफल विशिष्टता स्तर भार परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।'' मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षण से उच्च क्षमता वाले 'रिबन पैराशूट' के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता साबित हुई।

यह परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डीआरडीओ के 'एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट' और टीबीआरएल की विभिन्न टीमों के सहयोग से आयोजित किया गया।

आरटीआरएस एक विशेष गतिशील परीक्षण प्रतिष्ठान है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वायुगतिकीय और बैलिस्टिक मूल्यांकन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगनयान 'ड्रोग पैराशूट' के सफल विशिष्टता परीक्षण पर डीआरडीओ, इसरो और उद्योग जगत की सराहना की है।

उन्होंने कहा कि यह परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने भी परीक्षण में शामिल टीमों को बधाई दी।

पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने को एक बड़ा आंदोलन बनाने की जरूरत : चौहान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को पर्यावरण बचाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पेड़ लगाने को एक बड़ा आंदोलन बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वह हर दिन कम से कम एक पौधा लगाने के अपने वादे के पांच साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

चौहान ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। उन्होंने 19 फरवरी, 2021 को नर्मदा जयंती के मौके पर अमरकंटक में 'रुद्राक्ष' और 'साल' के पौधे लगाकर इस हरित पहल की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने पिछले पांच साल में 6,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, चौहान ने घोषणा किया कि उनके दोनों मंत्रियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रम पौधे लगाने से शुरू होंगे। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधिकारियों को भी ऐसा ही करने का निर्देश दिया। ऐसे कार्यक्रम में खास लोगों के सम्मान में पौधे दिए जाने चाहिए।

अपने वादे के पांच साल पूरे होने पर, मंत्री ने पेड़ लगाने को एक बड़ा आंदोलन बनाने के लिए एक 'मंच' बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कहा कि वह इस दिशा में काम करेंगे।

'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' ने नए युग के लिए नैतिक दिशा तय की : अमित शाह

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' ने नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर देश को एक नये युग में नेतृत्व के लिए तैयार किया है। शाह ने 'एक्स' पर की गई कई पोस्ट में कहा कि वैश्विक नेताओं और तकनीकी दिग्गजों के सबसे बड़े सम्मेलन की मेजबानी करके, भारत ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के प्राचीन मंत्र के साथ नये युग के लिए नैतिक दिशा तय कर रहा है।

गृह मंत्री ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन ''भारत का दुनिया से किया गया ऐसा वादा है, जिसके माध्यम से वह अपनी नवाचार की असीम क्षमता और संस्कृति में गहराई तक रची-बसी लोकतांत्रिक भावना के बल पर मानवता की प्रगति की यात्रा को निरंतर गति प्रदान करेगा।'' उन्होंने कहा, ''भविष्य भले ही कई लोगों के लिए अनिश्चित हो, लेकिन भारत ने पहले ही अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली है।'' शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मेलन में प्रस्तुत भारत की एआई परिकल्पना मानवता को एक त्रुटिरहित भविष्य की ओर दिशा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि नैतिकता, जवाबदेही, राष्ट्रीय डाटा संप्रभुता, सुलभता और विश्वसनीय प्रणालियों के सिद्धांतों के साथ दुनिया सभ्यतागत छलांग लगाने के लिए तैयार है।

20-02-2026 सूर्यास्त 6:15 बजे | 21-02-2026 सूर्योदय 6:29 बजे

	BSE	NSE
	82,498.14 (-1,236.11)	25,454.35 (-365.00)

सोना	चांदी
16,192 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	258,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

बेमेल गठबंधन

जब भी होता है गठबंधन,
जुड़ते उसमें अवसरवादी।
दोषारोपण इक दूजे पर,
करने वाले हैं बकवादी।
हैं सभी सियासत की चालें,
वादी ना कोई प्रतिवादी।
जैसे मजबूरी में कोई,
करता है अनचाही शादी।।

एआई सम्मेलन के मंच पर फोटो के दौरान 'असमंजस' में दिखे ओपनएआई और एंथ्रोपिक के सीईओ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के मंच पर एक समूह फोटो के दौरान बृहस्पतिवार को थोड़ी असहज स्थिति का सामना करने वाले ओपनएआई के मुखिया सैम ऑल्टमैन ने कहा कि वह 'थोड़ा भ्रमित हो गए थे' और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस समय क्या करना है।

ऑल्टमैन को शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के बाद मंच पर साथी तकनीकी दिग्गजों के साथ एक समूह फोटो लिए जाने के दौरान असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था।

उस दौरान मंच पर ओपनएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ऑल्टमैन के साथ एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी मौजूद थे।

इनके अलावा मेटा के मुख्य एआई अधिकारी अलेक्जेंडर वांग, सर्वम के सह-संस्थापक प्रत्यूष कुमार और गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस भी खड़े थे।

फोटो क्लिक करते समय प्रधानमंत्री ने पिचाई और ऑल्टमैन के हाथ उठाए, जबकि ऑल्टमैन के बगल में खड़े अमोडेई इस बात को लेकर असमंजस में नजर आए कि उन्हें हाथ मिलाना है, हाथ पकड़ना है या केवल फोटो के लिए खड़ा रहना है। जहां अन्य प्रतिभागियों ने एक-दूसरे के हाथ उठाए, वहीं आल्टमैन एवं अमोडेई अंततः मुट्ठियां उठाए नजर आए।

बाद में इस घटना के बारे में पूछे जाने पर ऑल्टमैन ने कहा, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। मैं थोड़ा भ्रमित था। (प्रधानमंत्री) मोदी ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया और मुझे पता नहीं था कि हमें क्या करना है।''

ऑल्टमैन वर्ष 2019 से अमेरिकी एआई शोध संगठन ओपनएआई के सीईओ हैं और उनके नेतृत्व में ही लोकप्रिय एआई टूल चैटजीपीटी को पेश किया गया। वहीं अमोडेई ने क्लॉड मॉडल के लिए मशहूर एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सह-संस्थापक एवं सीईओ हैं। वैसे, ऑल्टमैन एवं अमोडेई पहले एक ही कंपनी में साथ काम कर चुके हैं। वर्ष 2020 में अमोडेई ने अपनी बहन डेनिएला अमोडेई और कुछ अन्य वरिष्ठ शोधकर्ताओं के साथ ओपनएआई से अलग होकर एंथ्रोपिक की स्थापना की थी।

दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा समय के साथ व्यावसायिक स्तर पर तेज होती गई है। नवंबर, 2023 में ऑल्टमैन को ओपनएआई के सीईओ पद से हटाए जाने के बाद कंपनी के बोर्ड ने कथित तौर पर अमोडेई से संपर्क किया था लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हालांकि, कुछ दिन बाद ही ऑल्टमैन को दोबारा ओपनएआई का सीईओ बना दिया गया था।

'प्रौद्योगिकी के साथ मानवता': फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने समावेशी एआई की वकालत की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक ढांचा तैयार करने पर काम करेंगे जिसमें नवाचार को जिम्मेदारी के साथ और प्रौद्योगिकी को मानवता के साथ जोड़ा जाएगा। मैक्रों ने कहा कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच सभी डिजिटल उपकरणों को समावेशी दृष्टिकोण की तरफ निर्देशित करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

यहां 'एआई इम्पैक्ट समिट' में अपने संबोधन में मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और भारत 'संप्रभु एआई' विकसित करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा करना और सभी के लिए समृद्धि को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, ''ऐसे समय में जब तनाव बढ़ रहा है, हमारे सभी डिजिटल उपकरणों को इस समावेशी दृष्टिकोण की तरफ निर्देशित करने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। वास्तव में, ऐसा करने से न केवल भारत में बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप में भी मजबूती आएगी।'' उन्होंने कहा, ''आइए मिलकर विभाजन के बजाय सेतु बनाने, विनाश के बजाय सृजन करने और लेने के बजाय साझा करने पर ध्यान केंद्रित करें। फ्रांस जी7 की अपनी अध्यक्षता का उपयोग इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए करेगा।'' मैक्रों ने कहा कि जी7 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में फ्रांस बच्चों को एआई और डिजिटल दुर्व्यवहार की चपेट में आने से बचाने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा, ''इसीलिए फ्रांस में हम 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम आज यहां मौजूद कुछ यूरोपीय देशों के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनमें ग्रीस और स्पेन शामिल हैं।''

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा, ''मुझे पता है, प्रधानमंत्री जी, आप भी इस क्लब में शामिल होंगे। यह बहुत अच्छी खबर है कि भारत बच्चों और किशोरों की सुरक्षा के लिए इस तरह का कदम उठाएगा। हम अपने युवा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं।''

एआई कंपनियों, भारतीय नवोन्मेषकों का संकल्प समावेशी एवं जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देना: वैष्णव

नई दिल्ली/भाषा। कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़ी अग्रणी कंपनियों और भारत के नवोन्मेषकों ने 'नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स' के तहत रोजगार सहित विभिन्न नीतिगत मुद्दों के समर्थन में वास्तविक दुनिया में एआई के उपयोग की समझ बढ़ाने तथा बहुभाषी और संदर्भ-आधारित मूल्यांकन को मजबूत करने का संकल्प किया है।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के निष्कर्षों की घोषणा करते बृहस्पतिवार को हुए कहा कि 'नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स' के तहत अग्रणी एआई कंपनियां और भारत के नवोन्मेषक जैसे सर्वम, भारतजन, यानी और सोकेट...एक साझा दृष्टिकोण के साथ स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के समूह पर सहमत हुए हैं जो समावेशी एवं जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, यह पहल एआई के काम करने के तरीके पर 'ग्लोबल साउथ' नीत दृष्टिकोण के निर्माण में भारत को अग्रणी बनाएगी जो नवाचार को समानता एवं वास्तविक प्रभाव के साथ संतुलित करती है।''

एआई को मोबाइल, इंटरनेट की तरह सस्ता बनाएंगे, 10 लाख करोड़ रु. का निवेश करेंगे : मुकेश अंबानी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अगले सात वर्ष में कृत्रिम मेधा (एआई) में 10 लाख करोड़ रु. के निवेश की बृहस्पतिवार को घोषणा की और वादा किया कि वह एआई को भारत में उसी तरह सस्ता व सुलभ बनाएंगे जैसे मोबाइल व इंटरनेट डेटा को बनाया था।

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' 2026 में अंबानी ने कहा कि यह पहल हर नागरिक, व्यवसाय और सरकारी सेवा को एआई से जोड़ेगी, जो जियो की डिजिटल क्रांति के परिवर्तनकारी पैमाने को दर्शाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अंबानी ने कहा, '' जियो ने भारत को इंटरनेट युग से जोड़ा। जियो अब भारत को बुद्धिमता (इंटेलिजेंस) के युग से जोड़ेगी... भारत अब बुद्धिमता को किराये पर लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए, हम बुद्धिमता से हासिल जानकारी की लागत को उतनी ही तेजी से कम करेंगे जितनी हमने डेटा के मामले में की थी।'' सात वर्ष में कुल 10 लाख करोड़ रुपए का यह निवेश तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित होगा। जामनगर में गीगावाट-पैमाने वाले एआई-तैयार डेटा सेंटर, जो 10 गीगावाट तक की हरित ऊर्जा अधिशेष का लाभ उठाएंगे। इसके अलावा एक राष्ट्रव्यापी 'एज-कंप्यूट लेयर' दूरसंचार एवं डिजिटल संचालक जियो के नेटवर्क के साथ एकीकृत होगी ताकि पूरे भारत में कम विलंबता वाली एआई सेवाएं प्रदान की जा सकें।

उन्होंने कहा, '' जियो, रिलायंस के साथ मिलकर अगले सात साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी।'' अंबानी ने कहा, '' यह कोई जोखिमपूर्ण निवेश नहीं है। यह मूल्यांकन के लिए नहीं है। यह धैर्यपूर्ण, अनुशासित राष्ट्र निर्माण में लगाई जा रही पूंजी है।'' उन्होंने कहा कि दूरसंचार संचालक जियो, भारत के एआई बदलाव में और भी बड़ी भूमिका निभाएगी और यह प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक क्षेत्र, सामाजिक विकास के प्रत्येक पहलू और सरकार की प्रत्येक सेवा को बुद्धिमत्ता प्रदान करेगी। अंबानी ने कहा, '' जियो उसी विश्वसनीयता, गुणवत्ता, व्यापकता एवं अत्यधिक सस्ती कीमत के साथ ऐसा करेगी जिसने संपर्क में क्रांति ला दी है। भारत बुद्धिमत्ता को किराये पर लेने का जोखिम नहीं उठा सकता।'' उन्होंने कहा, '' इसलिए, हम इसकी लागत को उतनी ही तेजी से कम करेंगे जितनी तेजी से हमने डेटा की लागत को कम किया था।''

जियो इंटेलिजेंस, भारत के लिए संप्रभु कंप्यूट अवसंरचना का निर्माण करेगी जिसमें गीगावॉट-स्तर के डेटा सेंटर, 10 गीगावाट तक तैयार हरित ऊर्जा और जियो के नेटवर्क के साथ गहराई से एकीकृत एक एज-कंप्यूट लेयर शामिल होगी।

भारत एआई के क्षेत्र में बन सकता है दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश : रिशद प्रेमजी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विप्रो लिमिटेड के कार्यकारी चेयरमैन रिशद प्रेमजी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के पास कृत्रिम मेधा (एआई) के अनुप्रयोग के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक बनने का अवसर है। प्रेमजी ने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र में भारत की बढ़त उन विकल्पों से तय होगी, जो वह प्रौद्योगिकी की इस नई लहर को लागू करने, इसके विस्तार और जिम्मेदारी के साथ इसके उपयोग के संबंध में चुनेगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपनी क्षमताओं को वास्तविक प्रभाव में बदलना अनिवार्य है।

'एआई इम्पैक्ट समिट' को संबोधित करते हुए प्रेमजी ने कहा कि एआई पीढ़ी में एक बार आने वाली ऐसी प्रौद्योगिकी है जो न केवल हमारे काम करने के तरीके को बदलती है, बल्कि यह भी बदल देती है कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''अगले कुछ वर्षों में भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, इससे न केवल हमारा आर्थिक भविष्य तय होगा, बल्कि एक अरब से अधिक लोगों की समस्याओं को हल करने की हमारी क्षमता भी आकार लेगी।'' प्रेमजी ने कहा कि एआई पर चर्चा अब संभावनाओं से हटकर व्यावहारिकता और इसे अपनाने पर केंद्रित हो गई है। उन्होंने कहा, ''इसका अर्थ यह है कि भारत के पास केवल इस प्रौद्योगिकी का निर्माता बनने का नहीं, पूरी दुनिया में एआई के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली केंद्रों में से एक बनने का अवसर है। यह एक ऐसी जगह होगी जहां एआई को वास्तविक दुनिया की जटिलताओं के बीच परखा जा सके और इसे व्यापक स्तर पर सफल बनाया जाए।'' उन्होंने कहा, ''आगे की ओर देखें तो एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़त केवल हमारे मॉडल के आकार या बुनियादी ढांचे के पैमाने से तय नहीं होगी। यह उन विकल्पों से तय होगी जो हम इस बारे में चुनेंगे कि एआई को कहां लागू करना है, इसका विस्तार कैसे करना है और इसे कितनी जिम्मेदारी के साथ तैनात किया जाना है, ताकि हम अपनी क्षमता को सरकारों, नागरिकों और उद्यमों के लिए वास्तविक प्रभाव में बदल सकें।''

टाटा समूह एआई चिप के विकास की दिशा में सक्रिय: चंद्रशेखरन

नई दिल्ली/भाषा। टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि समूह कृत्रिम मेधा (एआई) के समूचे प्रौद्योगिकी ढांचे के विकास पर काम कर रहा है और उद्योग-विशिष्ट एआई चिप विकसित करने की दिशा में भी पहल शुरू कर दी गई है। चंद्रशेखरन ने यहां आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों पर एआई के व्यापक प्रभाव को देखते हुए टाटा समूह औद्योगिक समाधानों से लेकर डेटा सेंटर और क्षेत्र-विशिष्ट एआई समाधानों तक कई स्तरों पर अपनी क्षमता विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा, हम समय के साथ उद्योग के हिसाब से अलग-अलग एआई-आधारित चिप विकसित करना चाहते हैं। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है, हालांकि इसकी समय-सीमा बताना अभी संभव नहीं है। समूह द्वारा विकसित किए जा रहे शुरुआती सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल वाहन क्षेत्र में किए जाने की संभावना है। टाटा समूह ने एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए अमेरिकी कंपनी ओपनएआई के साथ साझेदारी की है। इसके तहत शुरुआत में 100 मेगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर एक गीगावाट तक किया जा सकता है।

महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए पदोन्नति मानदंडों में ढील दी

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधीन सरकारी और सहायता प्राप्त डिप्लोमा एवं डिग्री संस्थानों में शिक्षकों के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत कई पात्रता शर्तों में काफी हद तक ढील दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी बृहस्पतिवार को दी।

इस राहत से यह सुनिश्चित होगा कि संविदात्मक या अस्थायी नियुक्तियों के बाद नियमित किए गए कुछ व्याख्याताओं को सीएएस लाभ पूर्व के अनुरूप ही प्रदान किए जाएं। इन व्याख्याताओं को 'रिफ्रेशर कोर्स' पूरा करने के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया गया था।

सरकार ने पांच मार्च, 2010 से पहले नियुक्त व्याख्याताओं के लिए सीएएस के तहत उच्च वेतनमान में नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश के जरिये पदोन्नति के लिए शैक्षणिक, प्रशिक्षण और योग्यता संबंधी आवश्यकताओं में नई छूट दी गई।

केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर 'आप' सरकार पर निशाना साधा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में कथित तौर पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की बृहस्पतिवार को आलोचना करते हुए दावा किया कि 2027 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य में कोई भी गैंगस्टर नजर नहीं आयेगा और उन्होंने अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वादा किया।

बिट्टू ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि क्या वहां कोई यह दावा करेगा कि गैंगस्टर अब भी खुलेआम अपनी गतिविधियों को

अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ये टिप्पणियां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कीं।

बिट्टू ने तरन तारन में आम आदमी पार्टी (आप) के एक सरपंच की हाल में हुई हत्या के बारे में पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और सुरक्षा बनाये रखने की 'आप' सरकार की क्षमता पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि सरपंच की हत्या का तरीका पंजाब की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि यह सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई कर पायेगी।'' उन्होंने सवाल किया, ''अपराधियों के लिए शादी के स्थल में घुसकर हत्या करना कैसे संभव है?''

'आप' के सरपंच हरबरिंदर सिंह की बुधवार को तरन तारन जिले में एक शादी समारोह के दौरान दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना अमृतसर जिले के वल्टोहा गांव के एक अन्य सरपंच और 'आप' के नेता झरमल सिंह की एक शादी समारोह के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने के लगभग एक महीने बाद हुई है।

हैदराबाद में तीन लोगों ने 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया

हैदराबाद/भाषा। हैदराबाद में दो नाबालिग समेत तीन लोगों ने चाकू दिखा कर 16 वर्षीय एक लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। चेंगिचेरला इलाके में स्थित एक घर में 16 फरवरी की रात यह घटना घटी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक को 18 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ पहले से ही डकैती और चोरी समेत आठ मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इसके साथ ही लड़की को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाने वाले नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लिया गया। अपराध में शामिल एक अन्य नाबालिग लड़का अब भी फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां ने 17 फरवरी को नरसिंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी 16 फरवरी को स्कूल के लिए निकली थी और घर नहीं लौटी। शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जांच के दौरान 18 फरवरी को चेंगिचेरला में लड़की का पता चला और उसे मुक्त करा लिया गया। जांच में पता चला कि सात फरवरी को नाबालिग लड़की खरीदारी के लिए चारमीनार इलाके में गई थी और वहां उसकी मुलाकात 16 वर्षीय एक लड़के से हुई।

आयात पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का एआई ढांचा बनाए भारत : जीत अदाणी

नई दिल्ली/भाषा। अदाणी समूह के कार्यकारी निदेशक जीत अदाणी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को आयात पर निर्भर रहने के बजाय अपना स्वयं का कृत्रिम मेधा (एआई) बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई आने वाले समय में राष्ट्रीय संप्रभुता को नए सिरे से परिभाषित करेगा। कारोबारी दिग्गज गौतम अदाणी के छोटे पुत्र जीत अदाणी ने भारत की 'इंटेलिजेंस सेंचुरी' (बौद्धिक सदी) का खाका पेश करते हुए संप्रभुता के तीन प्रमुख स्तंभों ऊर्जा, कंप्यूट और क्लाउड, तथा सेवाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये तीनों भारत की एआई रणनीति के केंद्र में हैं।

यहां 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में अदाणी ने कहा कि अपने एआई भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत को ऊर्जा और कंप्यूटिंग सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। उन्होंने अक्षय ऊर्जा समूहों को एआई डेटा केंद्रों और औद्योगिक गलियारों के साथ एकीकृत करने की योजनाओं का विवरण देते हुए कहा, एआई कोड में लिखा जाता है, लेकिन यह बिजली से संचालित होता है... इसलिए ऊर्जा सुरक्षा ही वास्तव में बौद्धिक सुरक्षा है। टिकाऊ ऊर्जा हमारे लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनेगी। कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे पर उन्होंने कहा, ''क्लाउड संप्रभुता का अर्थ अलगाव नहीं, बल्कि स्वायत्तता है। भारत को अपनी महत्वपूर्ण एआई जरूरतों को घरेलू स्तर पर ही पूरा करना चाहिए। हमारे स्टार्टअप, शिक्षा जगत, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए उच्च-क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधाओं तक स्वदेशी पहुंच होनी चाहिए।''

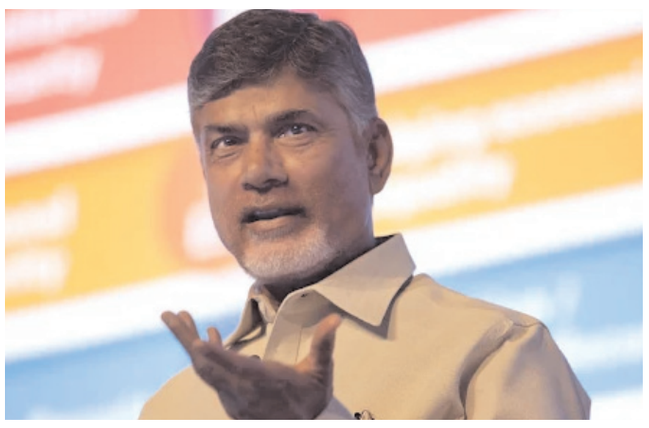

आंध्र प्रदेश में 29,000 करोड़ रुपए के निवेश के 27 प्रस्तावों को मंजूरी

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश निवेश संवर्धन बोर्ड की बैठक में 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश वाले 27 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

बुधवार देर रात एक सरकारी बयान में कहा गया, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई 15वीं राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) की बैठक में 29,021 करोड़ रुपए के निवेश वाले 27 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।

प्रशासन में बदलाव पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़े सभी मामलों में 'व्यवसाय करने की गति' नीति ही मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रहनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि 15 एसआईपीबी बैठकों में, आंध्र प्रदेश ने नौ लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश को मंज़ूरी दी है, जिससे 8.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। नायडू ने ज़ोर देकर कहा कि गूगल, आर्सेलरमित्तल और बीपीसीएल जैसी दिग्गज कंपनियों की विशाल परियोजनाएं विचाराधीन हैं और अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि सरकार की तरफ से कोई रुकावट न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों की एक समिति को कंपनियों को ज़मीन के आवंटन पर नज़र रखनी चाहिए और 'अगर कोई कंपनी काम शुरू नहीं करती है तो मंज़ूरी निरस्त कर देनी चाहिए।'

तेलंगाना में सामाजिक कल्याण और सभी के लिए न्याय का हमारा संकल्प दृढ़ है : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तेलंगाना के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की शानदार जीत के बाद बृहस्पतिवार को प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि प्रदेश में सामाजिक कल्याण तथा 'सभी के लिए न्याय' के संकल्प को लेकर पार्टी दृढ़ संकल्पित है।

खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, प्रदेश प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ तथा कई अन्य नेता शामिल हुए।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस बैठक में भाग लिया।

खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में हमारी शानदार जीत के बाद, हमने एक व्यापक समीक्षा की, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को ''प्रजाला तेलंगाना'' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कहा।''

उन्होंने कहा, ''सामाजिक कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण और सभी के लिए न्याय का हमारा संकल्प दृढ़ है और हमारी गारंटी में परिलक्षित होता है। हम प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को साकार करने और वास्तव में समावेशी तेलंगाना का निर्माण करने का प्रयास जारी रखेंगे।''

तेलंगाना की 116 नगरपालिकाओं और सात नगर निगमों के लिए 11 फरवरी को मतदान हुआ था। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 2,582 वार्ड में से 1,300 से अधिक पर जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया।

वहीं, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को लगभग 700 और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को करीब 275 वार्ड में जीत हासिल हुई।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बैठक में तेलंगाना में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए

आवश्यक कार्य योजना, पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए विकास और कल्याण कार्यक्रमों और हाल के नगरपालिका और ग्राम पंचायत चुनावों के परिणामों पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव परिणामों पर संतोष व्यक्त किया है।

उनके मुताबिक, खरगे ने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कल्याण और विकास कार्यक्रमों की सार्वजनिक स्वीकृति को दर्शाते हैं।

रेवंत रेड्डी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''राहुल गांधी ने विशेष रूप से तेलंगाना के किसानों द्वारा कृषि क्षेत्र और 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल' में की गई प्रगति के बारे में जानकारी ली और कई सुझाव दिए।'''

राज्य सरकार वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यंग इंडिया आवासीय विद्यालय का निर्माण कर रही है, जहां गरीब छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है।

कांग्रेस नेतृत्व ने गुजरात की प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक की, जिसमें संगठन की स्थिति और राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस बैठक में खरगे और राहुल गांधी के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा और कई अन्य नेता शामिल हुए। गुजरात में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होगा।

द्रमुक नीत गठबंधन में शामिल हुई डीएमडीके

भाजपा ने विजयकांत के कदम की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव एलायंस (एसपीए) में शामिल दलों ने डीएमडीके के गठबंधन में शामिल होने का बृहस्पतिवार को स्वागत किया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि द्रमुक के साथ गठबंधन करने के फैसले के लिए अभिनेता विजयकांत की 'आत्मा' माफ नहीं करेगी। इससे पहले दिन में, दिवंगत अभिनेता विजयकांत द्वारा स्थापित देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम (डीएमडीके) ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए एसपीए में शामिल होने की घोषणा की थी।

प्रेमलता विजयकांत के नेतृत्व वाली डीएमडीके द्वारा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की पेशकश को छोड़ उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्रमुक के साथ जाने को राजग के लिए एक झटका माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अन्नाद्रमुक डीएमडीके को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। द्रमुक नीत गठबंधन में शामिल कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई ने कहा कि डीएमडीके का एसपीए में शामिल होना राज्य की राजनीति में 'एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम' है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगई ने कहा, ''आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएमडीके का द्रमुक नीत गठबंधन में शामिल होना तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।''

उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में कहा, ''(डीएमडीके महासचिव) प्रेमलता विजयकांत और डीएमडीके के पदाधिकारियों द्वारा लिए गए इस शानदार फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह गठबंधन सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा।'' एसपीए के एक अन्य घटक मारुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) के नेता वाइको ने इस घटनाक्रम को 'खुशनुमा खबर' करार दिया। उन्होंने मदुरै में संवाददाताओं से कहा, हम उनका सहर्ष स्वागत करते हैं। इस गठबंधन से एसपीए को मजबूती मिलती है। द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत इससे सुनिश्चित हो गई है।''

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे डीएमडीके संस्थापक की विरासत के साथ 'विश्वासघात' करार दिया। भाजपा ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि कैप्टन द्वारा शुरू किये गए आंदोलन को जनविरोधी द्रमुक के साथ खड़ा करने के फैसले को कैप्टन की आत्मा कभी माफ नहीं करेगी। डीएमडीके के संस्थापक को प्यार से 'कैप्टन' कहा जाता है। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने कहा, जहां तक मेरा मानना है , वे (डीएमडीके) एक डूबते जहाज पर सवार हो गए हैं।'' कैप्टन की विरासत के इतर कार्यकर्ताओं को एक ऐसे जहाज के कैप्टन के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया है जो पहले से ही डूब रहा है।

भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल तमिल मनीला कांग्रेस (टीएमसी) के अध्यक्ष जी.के. वासन ने कहा कि डीएमडीके और द्रमुक के बीच गठबंधन जनता की उम्मीदों के खिलाफ है। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में संवाददाताओं से कहा, कैप्टन के जीवित रहने तक उन्होंने कभी द्रमुक के साथ गठबंधन नहीं किया। लोग इस गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। अभिनय से राजनीति में आए विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने कहा कि डीएमडीके-द्रमुक गठबंधन को एक प्रतिशत लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे।

टीवीके के संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मल कुमार ने चेन्नई में संवाददाताओं से कहा, ''कैप्टन विजयकांत को द्रमुक की ओर से काफी अपमान सहना पड़ा और उन्होंने अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जब ये सभी गठबंधन सहयोगी एक मंच पर एकत्रित होंगे, तो एक प्रतिशत लोग भी उन पर विश्वास नहीं करेंगे। वे किसी भी कीमत पर इस गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे।'' अन्नाद्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने डीएमडीके को राज्यसभा सीट का आश्वासन पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा, ''डीएमडीके को साथ लाने के प्रयास किए गए थे, क्योंकि विजयकांत द्वारा गठित पार्टी शुरू से ही द्रमुक का विरोध करती रही है।''

भाजपा के एक पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन समेत वरिष्ठ नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर प्रयास किए थे कि प्रेमलता द्रमुक के साथ न जाएं। उन्होंने दावा किया कि दो पार्टियों से एक साथ बातचीत करने का उनका निर्णय संकेत देता है कि वे अधिक सीट प्राप्त करने की कोशिश कर रही थीं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉल्फिन श्रीधर ने कहा, ''डीएमडीके को अपने खेमे में शामिल करके द्रमुक अपने सहयोगी कांग्रेस को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसे आवंटित सीटों की संख्या स्वीकार कर लेनी चाहिए।'' इसी बीच, प्रेमलता ने द्रमुक के साथ अपने गठबंधन की घोषणा करने के बाद चेन्नई में कैप्टन के स्मारक पर प्रार्थना की और बाद में डीएमडीके मुख्यालय में आयोजित अन्नदानम (भंडारा) में हिस्सा लिया।

तमिलनाडु में महिला, बालिका सुरक्षा देश में सर्वश्रेष्ठ : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बृहस्पतिवार को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तमिलनाडु देश में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता नैनार नागेंद्रन के आरोपों पर कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में तमिलनाडु की स्थिति सर्वोत्तम है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में अधिक हो रही हैं।

नागेंद्रन ने सदन में आरोप लगाया कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के पिछले तीन वर्षों के शासन के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस पर हस्तक्षेप करते हुए स्टालिन ने कहा, यदि सदस्य तथ्यों को स्वीकार करने को तैयार हैं, तो मैं प्रमाण सहित स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं।

मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता से अन्य राज्यों, विशेषकर मणिपुर की स्थिति का भी उल्लेख करने को कहा। उन्होंने कहा, जब आप अन्य राज्यों से तुलना करते हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों की असुरक्षा तथा हिंसा की घटनाओं के संदर्भ में, तो तमिलनाडु सबसे सुरक्षित राज्य है। नागेंद्रन ने द्रमुक के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को समाप्त करने के वादे का मुद्दा भी उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, आपको यह मुद्दा उठाने का अधिकार है। आपकी पार्टी केंद्र में सत्ता में है। क्या आप अब इसे समाप्त करेंगे? भाजपा नेता ने तंज किया कि क्या राज्य सरकार को चुनाव से पहले ही 'गर्मी' का अहसास होता है, जब वह महिलाओं को 2,000 रुपये की ग्रीष्मकालीन अनुदान राशि वितरित करती है ? इस पर स्टालिन ने पलटवार करते हुए पूछा, भाजपा द्वारा प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपये देने के वादे का क्या हुआ?

विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में राज्य की उपलब्धियां आधिकारिक आंकड़ों से प्रमाणित हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है और अपराध की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सदन में हुई चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर वादाखिलाफी और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए। हालांकि, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के मामले में तमिलनाडु देश में अग्रणी है और राज्य सरकार इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।

लेखक वी.एस. अनिलकुमार के घर के बाहर पुष्पचक्र मिला

विपक्ष ने माकपा की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कन्नूर/भाषा। केरल के कन्नूर स्थित कन्नापुरम में बृहस्पतिवार को लेखक और आलोचक वी.एस. अनिलकुमार के घर के बाहर एक पुष्पचक्र रखा हुआ मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। अनिलकुमार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के निष्कासित नेता वी कुन्हीकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त हुई थी। कुन्हीकृष्णन ने आरोप लगाया था कि पय्यानूर से पार्टी विधायक टी आई मधुसूदनन ने वामपंथी पार्टी के एक दिवंगत कार्यकर्ता के परिवार की सहायता के लिए एकत्र किए गए एक करोड़ रुपये का गबन किया था।

कन्नापुरम पुलिस थाने के अधिकारियों के अनुसार, अनिलकुमार ने सुबह अपने घर के गेट के पास पुष्पचक्र मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि अनिलकुमार के बेटे ने फुटबॉल कोचिंग के लिए घर से निकलते समय सबसे पहले पुष्पचक्र देखा। पुलिस के अनुसार, अनिलकुमार ने अपनी शिकायत में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संदेह नहीं जताया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के तहत घर और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे जाएंगे और लेखक का विस्तृत बयान लेने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। अनिलकुमार ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार, दोनों की आलोचना की थी। उन्होंने कुन्हीकृष्णन द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर पय्यानूर में माकपा के खिलाफ भी रुख अपनाया था। इस बीच, घटना के बाद कई लोगों ने अनिलकुमार के प्रति समर्थन व्यक्त किया। सुबह-सुबह फेसबुक पर उन्हें टैग करते हुए कई पोस्ट सामने आए, जिनमें लेखक के प्रति एकजुटता जाहिर की गई। इसी बीच, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने आरोप लगाया कि लेखक वी एस अनिलकुमार के घर के बाहर पुष्पचक्र रखने का कृत्य उस प्राचीन और हिंसक संस्कृति को दर्शाता है जिसे माकपा ने बनाए रखा है।

सतीशन ने कहा, प्रकाशित पुस्तक हासिल करने के विरुद्ध अनिलकुमार के घर के बाहर पुष्पचक्र रखा गया है। यह जान से मारने की धमकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी के समर्थकों द्वारा अंजाम दी गई थी। उन्होंने कहा, यह माकपा में आई गिरावट के स्तर को दर्शाता है।

टीवीके ने चुनावी तैयारी की तेज, 27 को जारी होगा घोषणा-पत्र

चेन्नई। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने चुनावी मैदान में संगठित प्रवेश का संकेत देते हुए 27 फरवरी को घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रारंभिक चरण में हर सीट के लिए तीन संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। संभावित उम्मीदवारों की सूची में लगभग 80 प्रतिशत नाम जिला सचिवों के हैं। इससे स्पष्ट है कि पार्टी जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना चाहती है और स्थानीय संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसके अलावा, राज्य स्तरीय पदाधिकारियों और अनुभवी प्रशासकों के नाम भी सूची में शामिल किए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति संगठनात्मक निष्ठा और प्रशासनिक अनुभव के संतुलन को दर्शाती है। कुछ हाई-प्रोफाइल सीटों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। विल्लिवक्कम में हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व अन्नाद्रमुक विधायक के बेटे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं कोलाथुर सीट पर एक प्रसिद्ध उद्योगपति के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। तेनकासी जिले में अलंगुलम क्षेत्र के एक प्रमुख थिएटर मालिक के बेटे और वासुदेवनल्लूर के पूर्व विधायक को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

सबसे अधिक चर्चा विजय की संभावित सीट को लेकर हो रही है। आधिकारिक घोषणा भले न हुई हो, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार वे वेदारण्यम से चुनाव लड़ सकते हैं, जो नागपट्टिनम जिले में स्थित है।

न्यायालय ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड को काम करने से रोकने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

चेन्नई/नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रकार के कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया था। उच्च न्यायाय ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा था कि बोर्ड का गठन प्रथम दृष्टया कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने तमिलनाडु सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर वक्फ बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय के 8 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब किया। उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने इसलिए वक्फ के कार्य करने पर रोक लगाई थी क्योंकि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता एवं विकास अधिनियम, 1995 की धारा 14 के खंड (डी) में अनिवार्य रूप से नामित दो व्यक्तियों में से एक को मनोनीत नहीं किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में यह भी दावा किया गया था कि धारा 14 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त बोर्ड के कुल सदस्यों में से दो सदस्यों का गैर-मुस्लिम होना अनिवार्य है, इस अनिवार्यता का पालन नहीं किया गया है (पदेन सदस्यों को छोड़कर)। अधिनियम की धारा 14 बोर्ड की संरचना से संबंधित है। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि बोर्ड का गठन लगभग पूरा हो चुका है क्योंकि अधिकांश सदस्यों को पहले ही मनोनीत या नियुक्त किया जा चुका है और अन्य सदस्यों के संबंध में, इसे पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि दूसरी शर्त का पालन नहीं किया गया, जिसके अनुसार उपधारा (1) के तहत नियुक्त बोर्ड के कुल सदस्यों में से दो सदस्यों का गैर-मुस्लिम होना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय ने कहा था, वर्तमान में बोर्ड का गठन प्रथम दृष्टया कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए, बोर्ड को अधिनियम के तहत किसी प्रकार की शक्तियां और कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने मुफ्त सुविधा संस्कृति की आलोचना की, कहा- राज्यों को रोजगार के अवसर खोलने चाहिए

नईदिल्ली/चेन्नई। उच्चतम न्यायालय ने लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।

'तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को नि:शुल्क बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।

शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य गरीबों की मदद करते हैं तो यह बात पूरी तरह से समझ में आती है। देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों का राजस्व घाटे में हैं लेकिन वे विकास की अनदेखी करते हुए इस तरह की मुफ्त सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की मुफ्त सुविधाएं देने से देश के आर्थिक विकास में बाधा पैदा होती है और राज्यों को सभी को मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली देने के बजाय रोजगार के अवसर खोलने के लिए काम करना चाहिए।

शबरिमला में सोने की चोरी मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए : राजीव चंद्रशेखर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को कहा कि शबरिमला से सोने की कथित तौर पर चोरी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को करनी चाहिए क्योंकि यह एक बड़ा अपराध है और विशेष जांच दल (एसआईटी) अब तक इस मामले में कुछ भी करने में असमर्थ रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया था लेकिन मार्क्सवादी नेता ने ऐसा नहीं किया। भाजपा नेता ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मैं मुख्यमंत्री से एक बार फिर विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की सीबीआई जांच कराएं ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री वास्तव में यह पता लगाना चाहते हैं कि भगवान अयप्पा मंदिर से सोने की कथित तौर पर चोरी के पीछे कौन था, तो उन्हें सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए।

उन्होंने कहा, सरकार मंदिर से सोने की चोरी के पीछे के लोगों का पता नहीं लगा पाई। एसआईटी को भी कुछ नहीं मिला। यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से जुड़ा एक बड़ा अपराध है। सीबीआई ही इसकी जांच करने के लिए सबसे सक्षम एजेंसी है। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि सतर्कता न्यायालय ने बुधवार को शबरिमला के मुख्य पुजारी कंदारारु राजीव को जमानत देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

चंद्रशेखर ने कहा, इसलिए, सोने की चोरी के दोषियों को ढूंढना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर ने 'द केरल स्टोरी' फिल्म के दूसरे भाग की आलोचना करने के लिए विजयन पर निशाना साधा और उन पर 'दोहरा मापदंड' अपनाने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अलग-अलग व्याख्या' करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2023 में मलप्पुरम में आयोजित फलस्तीन समर्थित एक कार्यक्रम में हमास नेता की ऑनलाइन भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा, जब हमास यहां आकर अपने भाषणों से हमारे युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करता है, तो मुख्यमंत्री इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं।

भाजपा नेता ने कहा, लेकिन अगर कोई लव जिहाद' पर फिल्म बनाता है, तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 कहां जाता है? मुझे मुख्यमंत्री के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सब उनकी अलग-अलग व्याख्या है। अगर मुख्यमंत्री को फिल्म पसंद नहीं है, तो इसे न देखें। जो देखना चाहते हैं, वे देख सकते हैं। चंद्रशेखर ने दावा किया कि जब उन्होंने हमास के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्हें सांप्रदायिक कहा गया।

उन्होंने जोर देकर कहा, क्या फिल्म के खिलाफ बोलने के लिए मुझे मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक कहना चाहिए? यह उनके दोहरे मापदंड को दर्शाता है। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, तो वह कुछ सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। अगर हमास को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो 'केरल स्टोरी' फिल्म के निर्माताओं को भी होनी चाहिए। भाजपा ऐसे दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं करेगी।

REGIONAL RESEARCH INSTITUTE OF UNANI MEDICINE, CHENNAI
No.1, West Mada Church Road, Royapuram, Chennai -13
(NABH Accredited)
(A Unit of Central Council for Research in Unani Medicine)
Ministry of Ayush, Govt. of India, New Delhi

Advertisement No. 1/2026
Walk-in-Interview

Eligible candidates are invited for Walk-in-Interview for engagement on purely contractual basis to the following posts at RRIUM, Chennai on the under mentioned date and time.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Date & Time of Interview
1.	RESEARCH ASSOCIATE (Bio-informatics)	1 No.	07-03-2026 @ 09.00 a.m

Details of requirements, qualifications and experience are available on the Websites: **ccrum.res.in / rriumchennai.org**

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एवं सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने युवाओं से किया संवाद

एनसीसी कैडेट्स, स्कूली एवं मूक बधिर विद्यार्थियों को किया प्रेरित

एचसीएम रीपा के भगवत सिंह मेहता सभागार में हुआ संवाद कार्यक्रम

भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स से रूबरू होकर रोमांचित हुए युवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। भारतीय वायु सेना की ब्रांड एंबेसडर टीमों सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने गुरुवार को जयपुर के युवाओं से संवाद कर उन्हें राष्ट्र सेवा, अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। संवाद कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एवं मूक-बधिर विद्यार्थी उपस्थित रहे। टीम सदस्यों ने विद्यार्थियों को वायुसेना में करियर के अवसरों, कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया, टीमवर्क और समर्पण के महत्व से अवगत कराया। साथ ही 20 एवं 22 फरवरी को जल महल की पाल पर प्रस्तावित भव्य एयर शो की जानकारी साझा की। पायलटों ने कहा कि जयपुरवासियों के लिए यह अवसर भारतीय वायुसेना के साहस, सटीकता और अनुशासन को सजीव रूप में देखने का यादगार क्षण होगा।

आयोजन में जानकारी दी गई कि वर्ष 1996 में स्थापित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम है और विश्व की चुनिंदा टीमों में शामिल है। यह टीम लाल-सफेद रंग के आकर्षक क्रुझ चझ-132 जेट विमानों पर उड़ान भरते हुए लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान तथा लोकप्रिय 'डीएनए' संरचना जैसे रोमांचक करतब प्रस्तुत करती है। अब तक 800 से अधिक प्रदर्शनों के माध्यम से टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अनेक देशों में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है।

टीम में 14 पायलट शामिल हैं। टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (सु-30 एमकेआई के अनुभवी पायलट) हैं तथा डेप्यूटी लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह हैं। अन्य पायलटों एवं तकनीकी अधिकारियों की समर्पित टीम सटीक गठन उड़ान को संभव बनाती है। उल्लेखनीय है कि टीम के तीन पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर से ही हैं। हाल ही में विमानों में स्वदेशी स्मोक पॉड्स का एकीकरण किया गया है, जिसे वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो, नासिक में विकसित किया गया है। इससे प्रदर्शन के दौरान आकाश में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा बिखेरी जा सकती है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है। आयोजन में यह भी जानकारी दी गई कि सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों और सटीक सामूहिक उड़ान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एरोस्पेस शो में पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति के बाद से टीम 390 से अधिक स्थलों पर 1200 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है।

टीम ध्रुव हेलिकॉप्टर का संचालन करती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह सर्व-मौसम और बहु-उद्देश्यीय क्षमता वाला हेलिकॉप्टर है, जो 'आत्मनिर्भरता' की भावना का सशक्त प्रतीक है। 20 फरवरी तक अभ्यास उड़ानों के पश्चात 22 फरवरी को जलमहल के ऊपर पाँच हेलिकॉप्टरों का भव्य सामूहिक प्रदर्शन जयपुरवासियों को रोमांचित करेगा।

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम का आदर्श वाक्य सदैव सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रतिबिंबित करता है। युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम ने न केवल उन्हें प्रेरित किया, बल्कि भारतीय वायुसेना के साहसिक एवं तकनीकी कौशल की झलक भी प्रस्तुत की। जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को इसी जोश और गौरव का साक्षी बनेगा।

जालोर में पारिवारिक विवाद के चलते व्यक्ति ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या की

जयपुर। राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल थाना क्षेत्र के दसपां गांव में बुधवार देर रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की कथित तौर पर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मगलाराम पुरोहित (40) के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मंगलाराम की पत्नी ददमी देवी (39), बेटी नीकू (10) और बेटा हितेश (7) चारपाई पर मृत पड़े थे और उनके गले पर चोट के निशान थे। पुलिस के मुताबिक, दीवारों पर भी खून के निशान थे। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान मंगलाराम ने पत्नी और बच्चों की हत्या की बात कबूल की है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और बच्चों की हत्या की। सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलाराम का बड़ा बेटा आंध्र प्रदेश में काम करता है, जबकि दूसरा बेटा मुकेश घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर अपने चाचा के घर सो रहा था। आरोपी किसान है और उसकी शादी को लगभग 20 साल हो चुके हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को मौके पर बुलाया गया और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

राजस्थान में उचित मूल्य की 841 नयी दुकानें खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन : गोदारा

जयपुर। राजस्थान में उचित मूल्य की 841 नयी दुकानें खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 841 नयी उचित मूल्य दुकानें खोलने के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जबकि 399 दुकानों की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी 15 नयी उचित मूल्य दुकानों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। गोदारा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2022-23 के बजट में 5000 खाद्य सुरक्षा उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की घोषणा की गई थी उनमें से केवल 531 दुकानें ही खोली गईं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रभान सिंह चौहान द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नियमानुसार न्यूनतम 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट पर एक उचित मूल्य दुकान खोले जाने का प्रावधान है।मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टरों को नियमों में शिथिलता के अधिकार प्रदान किए हैं, ताकि आवश्यकता अनुसार दुकानें खोली जा सकें।

उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को बम से उड़ाने की धमकी

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को बृहस्पतिवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद परिसर की तलाशी ली गई। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय प्रशासन से सूचना मिलने पर श्वान दस्ता और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और परिसर को खाली करवाकर तलाशी अभियान चलाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस घटना के कारण कुछ समय के लिए उच्च न्यायालय की नियमित कार्यवाही बाधित हुई। उच्च न्यायालय, स्कूलों और कॉलेजों को पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं, जो सभी झूठी साबित हुईं। आज की धमकी ऐसे समय आई है जब भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जयपुर दौरा प्रस्तावित है। सीजेआई शुक्रवार को एक सेमिनार का उद्घाटन करने के लिए जयपुर आने वाले हैं।

राजस्थान के कई इलाकों में बारिश

जयपुर। एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते चौबीस घंटे में राजस्थान के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी । इसके अनुसार, आज सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक बारिश शाहपुरा (जयपुर) में 22.0 मिलीमीटर हुई। न्यूनतम तापमान अलवर व फतेहपुर सीकर में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार, अब राज्य में मौसम साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

भीलवाड़ा में एसयूवी पलटने से दो लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बुधवार शाम एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) के पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, वाहन में सवार लोग शादी से पहले की रस्म 'मायरा' समारोह में शामिल होने टोंक जिले से जा रहे थे। फुलिया कलां थाना क्षेत्र में राज्यास के पास राजमार्ग पर अचानक आई भैंसों से बचने की कोशिश में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और वाहन में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके।

राहुल गांधी और 25 कांग्रेस सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति हिरासत में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दल के 25 अन्य सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला वीडियो जारी करने वाले एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को राजस्थान के कोटा में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी को बोरखेड़ा थाने में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

उन्होंने कहा, अभी तक किसी भी संगठन से उनके संबंधों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उद्योग नगर पुलिस थाने में उनके खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। संबंधित धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। खुद को दक्षिणपंथी समूह करणी सेना का प्रवक्ता राज सिंह बताने वाले व्यक्ति ने कथित वीडियो में कहा कि भाजपा और करणी सेना के सभी कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि हाल ही में संपन्न हुए संसद के बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में 25 कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपशब्द कहे। वीडियो में उसने कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम उन सांसदों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ करेंगे। मुझे लगता है कि यह सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। राहुल गांधी ध्यान से सुन लें, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम आपके घर में घुसकर आपको गोली मार देंगे। वीडियो में उसने आगे कहा, अगर उन सांसदों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम उन्हें एक-एक करके गोली मार देंगे।

वीडियो में वह सोफे पर बैठा दिखाई दे रहा है और पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथ मिलाने की एक तस्वीर लगी हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद कोटा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। भाजपा और करणी सेना दोनों ने सिंह के साथ किसी भी प्रकार के संबंध होने से इनकार किया। भाजपा कोटा शहर अध्यक्ष राकेश जैन ने स्पष्ट किया कि आरोपी व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भाजपा से जुड़ा नहीं है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की भाषा और आचरण हमारी विचारधारा और नैतिक मूल्यों के विपरीत है। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी कहा कि वीडियो जारी करने वाले व्यक्ति का करणी सेना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, करणी सेना ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें किसी की जान लेने की धमकी दी गई हो। हम विरोध करने, काले झंडे दिखाने, सड़कों पर उतरने की बात करते हैं, लेकिन किसी को मारने की नहीं। यह हमारी विचारधारा नहीं है।

मकराना ने आगे कहा, हमारे लिए नरेन्द्र मोदी उतने ही सम्माननीय हैं जितने राहुल गांधी। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम इस तरह की धमकियां नहीं देते। सार्वजनिक रूप से किसी की जान लेने की धमकी देने वाला व्यक्ति करणी सेना का सदस्य नहीं है।

मोदी की अजमेर यात्रा : मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लिया फीडबैक

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा से 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा के तहत प्रदेशवासियों को 23 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात देने के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। शर्मा बुधवार को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अजमेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कायड विश्राम स्थली पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां आपसी समन्वय से तय समय में पूरी करें। मुख्यमंत्री ने डोम, बैठक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने इस संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने वाले डीबीटी कार्यक्रम और लाभार्थियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली।

शिवाजी महाराज विश्व के अपराजेय योद्धा : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज विश्व के अपराजेय ऐसे योद्धा थे जिन्होंने निरंतर युद्ध लड़े और मुगल सल्तनत को चुनौती दी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंगों के आलोक में मातृभूमि के लिए संकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की स्मृति ही जोश जगाने वाली है।

बागड़े गुरुवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतिहास में भारतीय दृष्टि आरम्भ से ही गौण रही है। इसलिए हमारे देश के योद्धाओं, वीरों का इतिहास पूरी सच्चाई से लिखा नहीं गया। इसी से नई पीढ़ी भारत के गौरवमय इतिहास से वंचित है। शिवाजी जयंती समारोह की राजस्थान में इसलिए शुरुआत की गई है कि हम उनके जीवन आलोक से प्रेरणा ले सकें। राज्यपाल ने शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े पक्षों की विस्तार से चर्चा करते हुए उनके वंश और मूल जन्म स्थान आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी और तत्कालीन इतिहास से जुड़ी घटनाओं, शिवाजी की माता जीजाबाई और शिवाजी के रण कौशल को महत्वपूर्ण और प्रेरणादाई बताया।

बागड़े ने कहा कि अफजल खान जब शिवाजी महाराज को पकड़ने आया था तब वह प्रतापगढ़ में थे। शिवाजी ने उसे बहुत वीरता से वाघ-नख के वार से मार डाला। बीजापुर के आदिलशाही साम्राज्य को अपनी कुशल युद्धनीति, गोरिल्ला तकनीक और साहस से कमजोर कर शिवाजी महाराज ने कोंकण और पुणे के कई महत्वपूर्ण किले जीते। बीजापुर की सेना को कई बार हराया, जिससे आदिलशाही सल्तनत अंततः सिमट गई।

बागड़े ने राजस्थान की शौर्य धरा से भी युवाओं को सीख लेने का आह्वान किया। उन्होंने बप्पा रावल को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सबसे पहले खदेड़ा। इसके डेढ़ सौ, दो सौ साल तक मुगलों ने भारत की ओर नहीं देखा। उन्होंने राजस्थान के शेखावाटी अंचल की चर्चा करते हुए कहा कि वहां एक एक गांव के सैकड़ों सैनिक माँ भारती की सेवा के लिए सेना में जाते हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन आलोक से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को भारत के गौरवमय इतिहास से जुड़ने का भी आह्वान किया।

ईएसआई के तहत बीमित व्यक्तियों और परिजनों को मिले बेहतर सुविधाएं : अर्जुनराम मेघवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को बीकानेर के जैसलमेर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के समस्त वार्डों एवं व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया तथा प्रभारी सहित अन्य चिकित्सकों की बैठक ली। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ईएसआई के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिजनों को बेहतर और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह अस्पताल संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसके माध्यम से समयबद्ध और स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए तथा प्रत्येक श्रमिक तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसके मद्देनजर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए।

मेघवाल ने अस्पताल की दैनिक ओपीडी पर असंतोष जताया और कहा कि चिकित्सा प्रभारी द्वारा जिले के प्रमुख औद्योगिक संगठनों तथा संस्थानों से समन्वय करते हुए विशेष शिविर लगाए जाएं। जिससे बीमित व्यक्तियों को इस सुविधा की जानकारी मिल सके।

उन्होंने कहा कि यहां मशीनरी और मैन पावर नियोजन संबंधी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन केन्द्र सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र, शहर के प्रमुख स्थान पर है तथा यहां लाभांवित होने वाले मरीजों की संख्या की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जाती है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि बीकानेर का यह संस्थान आगे रहे। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ईएसआई के इस तीस बैडेड अस्पताल की साख किसी स्थिति में प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, सुविधाओं सहित सभी आवश्यकताओं की नियमित समीक्षा करें तथा इससे अवगत करवाएं। उन्होंने प्रमुख आवश्यकताओं के संबंध में नोट तैयार कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़े समय बाद सभी व्यवस्थाओं का पुनः फीडबैक लिया जाएगा।

राजसमंद में लापता महिला व नाबालिग बेटे का शव मिला

जयपुर/दक्षिण भारत । राजस्थान के राजसमंद जिले में हफ़्ते भर से लापता महिला का शव बृहस्पतिवार को एक तालाब में मिला। पुलिस ने बताया कि उसके नाबालिग बेटे का शव भी जंगली इलाके से बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों की हत्या कथित तौर पर गोविंद सिंह ने की। पीड़िता प्रियंका (22) इसी आरोपी के साथ 11 फरवरी की रात कहीं चली गई थी। भीम के थानाधिकारी ने बताया कि प्रियंका 11 फरवरी की रात को लापता हो गई थी और अगले दिन यानी 12 फरवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वह अपने डेढ़ साल के बेटे आर्यन के साथ-साथ घर से कुछ कीमती सामान लेकर गई थी।पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि वह गोविंद सिंह के साथ नियमित संपर्क में थी। संदेह होने पर गोविंद सिंह को बुधवार रात हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान उसने प्रियंका और उसके बेटे की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने दावा किया कि उसने महिला की लाश तालाब में और लड़के की लाश जंगल वाले इलाके में फेंक दी।

उप्र के दोनों उपमुख्यमंत्री संतों और बटुकों का सम्मान करते हैं : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

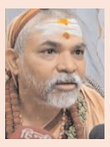

वाराणसी/लखनऊ/भाषा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री संतों और बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 40 दिनों के भीतर गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित नहीं किया गया तो संत लखनऊ तक मार्च करेंगे। वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए, अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में हाल में संपन्न माघ मेले के दौरान हुए उस विवाद के संबंध में उपमुख्यमंत्रियों– ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य – की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया, जहां कुछ बटुकों के साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने कहा कि पाठक ने बटुकों की चोटी को कथित तौर पर खींचने को ''गंभीर पाप'' करार दिया था और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अविमुक्तेश्वरानंद ने मौर्य की पिछली अपील का भी जिक्र किया जिसमें उनसे अपना विरोध समाप्त करने और मौनी अमावस्या पर संगम में पवित्र स्नान करने का आग्रह किया गया था।

न्यायालय ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनी से पूछा: क्या आपको पता है कि देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचा

नई दिल्ली/भाषा। जिस फार्मास्युटिकल कंपनी के कफ सिरप के सेवन से उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर 18 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी, उससे उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पूछा, ''क्या आपको पता है कि इससे देश की छवि को कितना नुकसान हुआ है?''

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने उस आदेश को रद्द करने से मना कर दिया, जिसमें कंपनी और उसके कुछ अधिकारियों को एक शिकायत पर तलब किया गया था, जिसमें मानक रहित दवाओं के विनिर्माण और बिक्री सहित कई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

बिहार के विधानसभा अध्यक्ष समेत 45 विधायकों के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती

पटना/भाषा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत 45 सदस्यों के निर्वाचन को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से पराजित प्रत्याशियों ने ये चुनाव याचिकाएं दायर की हैं और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रसाद ने कहा, ''आम तौर पर कोई भी चुनाव याचिका सीधे खारिज नहीं की जाती। प्रतिवादियों को नोटिस भेजे जाते हैं और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद न्यायालय आदेश पारित करता है।'' एक सवाल पर उन्होंने कहा, ''हां, गया टाउन सीट से प्रेम कुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। हालांकि, उनके मामले में अब तक नोटिस जारी नहीं हुआ है।''

भारत में इसी साल शुरू हो जाएगा दुर्लभ स्थायी चुंबक का उत्पादन: किशन रेड्डी

नई दिल्ली/भाषा। कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में इसी साल से दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम होगा। दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, पवन चक्कियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैमानिकी और रक्षा क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है।

रेड्डी ने यहां उद्योग मंडल फिक्की और खान मंत्रालय की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत सरकार दुखउल्लभ पृथ्वी तत्वों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, इस क्रम में इसी साल भारत में स्थायी चुंबकों का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी और अबू धाबी के युवराज ने द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को सराहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अबू धाबी के युवराज (क्राउन प्रिंस) शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने बृहस्पतिवार को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश प्रवाह की सराहना की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के 'सॉवरेन वेल्थ फंड' को भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' से इतर हुई बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की सराहना की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश प्रवाह की सराहना की और यूएई के सॉवरेन संपदा कोषों को भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसी क्रम में दोनों नेताओं ने आपसी लाभ के लिए साझेदारी को मजबूत करने को नए सॉवरेन फंड 'एल-इमाद' की क्षमता को भी रेखांकित किया। उन्होंने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा की।

दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया।

यह समझौता दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा और पेशेवर आदान-प्रदान, संस्थागत सहयोग, अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, फार्मास्युटिकल तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देगा।

युवराज ने एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी दी। भारत मंडपम में आयोजित इस पांच दिन के शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों सहित 500 से अधिक एआई दिग्गज और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की तेल अवीव यात्रा से पहले भारत-इजराइल ने रक्षा सहयोग के लिए एक और करार किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तेल अवीव/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इसी महीने के आखिर में होने वाली इजराइल यात्रा से पहले, भारत और इजराइल ने रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने और भविष्य की संगोष्ठियों तथा सहकारी पहलों सहित चल रही संयुक्त गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इजराइल के रक्षा मंत्रालय (आईएमओडी) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय (एसआईबीएटी) ने भारत और इजराइल के प्रमुख रक्षा उद्योगों के बीच बैठकों की सुविधा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आईएमओडी द्वारा जारी बयान में बताया गया कि एसआईबीएटी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) और भारत के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस सप्ताह अग्रणी भारतीय और इजराइली रक्षा कंपनियों के बीच एक संगोष्ठी और बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) बैठकों का आयोजन किया। बयान के मुताबिक, ''संगोष्ठी की अध्यक्षता एसआईबीएटी के निदेशक, ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) यायर कुलास ने किया और इसमें भारत के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी अद्यतन रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2026 – भारत की राष्ट्रीय रक्षा खरीद नीति की जानकारी देने के के लिए इजराइल और भारत की छोटी, मध्यम और बड़ी रक्षा कंपनियों को मंच प्रदान किया गया।'' आईएमओडी ने बताया, ''इस कार्यक्रम में 30 भारतीय और 26 इजराइली रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।'' भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसआईडीएम के महानिदेशक रमेश के. ने किया और इसमें इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह और इजराइल में भारत के रक्षा अताशे ग्रुप कैप्टन विजय पाटिल शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को दो दिवसीय इजराइल दौरे पर पहुंचेंगे। संभावना है कि वे अपनी बैठकों के दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हित के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

कांग्रेस ने असम में 30 लाख बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति दी : हिमंत

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य में अपने शासनकाल के दौरान 30 लाख बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख बीघा अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया है। निवर्तमान विधानसभा सत्र में अपना अंतिम भाषण देते हुए शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने राज्य के परिवर्तनकारी सफर को आगे बढ़ाने के लिए ''कांग्रेस की कई विरासत'' के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस ने 30 लाख बीघा (लगभग 10 लाख एकड़) वन भूमि अतिक्रमित करने की छूट दे दी थी। हमने 1.5 लाख बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा कर लिया है।'' बेदखली अभियान के दौरान आदिवासी परिवारों का एक भी घर नहीं तोड़ा गया, और उन्हें भूमि पट्टे पर दी गई है। हम कांग्रेस की विरासत से लड़ रहे हैं। हम कई मोर्चों पर उनकी विरासत से लड़ रहे हैं जिनमें, बाल विवाह, बहुविवाह, भ्रष्टाचार और भी बहुत कुछ शामिल है... आज असम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चमकता सितारा है।''

बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग ठुकराई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को करीब एक दशक पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून सभी दलों को साथ लेकर राज्य विधानसभा में पारित किया गया था।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद, जो सत्तारूढ़ राजग का हिस्सा हैं, ने नीति की समीक्षा की मांग करते हुए कहा था कि इससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह कानून राज्य विधानमंडल में सभी दलों को साथ लेकर पारित किया गया था और इसकी समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता।

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी समीक्षा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक मांझी ने बुधवार को कहा था कि शराबबंदी से राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, ''प्रतिबंध के बावजूद पड़ोसी राज्यों से महंगी शराब की 'होम डिलीवरी' धड़ल्ले से हो रही है। जनता का पैसा बाहर जा रहा है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।''

मांझी ने दावा किया, ''जहां अमीर लोग बिना किसी परेशानी के महंगी शराब खरीद सकते हैं, वहीं गरीब जहरीली शराब पीने को मजबूर हो जाते हैं। इसका असर खासकर दलित समुदाय, विशेष रूप से भुइयां मुसहरों पर पड़ रहा है।'' मधुबनी से विधायक आनंद ने कहा कि शराब सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना पूर्ण प्रतिबंध से अधिक प्रभावी हो सकता है। उन्होंने कहा, ''कानून रहना चाहिए या नहीं, यह अलग विषय है और यह मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार है। हालांकि मेरा मानना है कि इस कानून के कारण राज्य को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है।''

'भाजपा की सरकारों ने पिछले छह सप्ताह में हमारे नौ एआई वीडियो हटवाए'

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पिछले छह सप्ताह के दौरान 'एआई' निर्मित उसके नौ वीडियो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न मंचों से हटवाए हैं, जबकि उन्हें नियमों का पालन करके तैयार किया गया था।

पार्टी की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कृत्रिम मेधा (एआई) पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में वह एआई से डरते हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''पिछले छह हफ़्तों में कांग्रेस के एआई से बने नौ वीडियो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनकी केंद्र और राज्य सरकारों ने डिलीट करवाए हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि इन सारे वीडियो में क़ानून के तहत जो 'एआई डिस्क्लेमर' होना चाहिए वो है।''

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वीडियो में ''यह एआई से बनाया गया वीडिया'' लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि किसी को भी भ्रमित करने की कोई कोशिश नहीं की गई है।

राहुल के खिलाफ हिंसा की सुनियोजित साजिश, एक और गोडसे तैयार किया जा रहा : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने राजस्थान में एक व्यक्ति द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिए जाने संबंधी वीडियो का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि यह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसा की सुनियोजित साजिश है।

पार्टी के मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि पहले भी नाथूराम गोडसे तैयार किया गया था तथा आज फिर एक और गोडसे को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया जिसमें एक व्यक्ति को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देते सुना जा सकता है।

खेड़ा ने दावा किया, ''पूरा आरएसएस-भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्टरी है। तथाकथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग-थलग पड़ी घटना नहीं है। यह एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''पहले, किरेन रीजीजू ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में ओम बिरला का अपमान किया, जबकि उपलब्ध वीडियो फुटेज इस दावे का खंडन करती है, जिसमें ऐसा कोई अपमान दिखाई नहीं देता। बल्कि, उस दौरान लोकसभा अध्यक्ष को मुस्कराते हुए देखा जा सकता है।''

खेड़ा ने कहा, ''भाजपा सांसदों ने विभिन्न मंचों पर लगभग एक जैसी पंक्ति दोहरानी शुरू कर दी कि राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। यह विपक्ष को बदनाम करने और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर राहुल जी के खिलाफ हिंसा को वैध ठहराने का एक सुनियोजित अभियान है।''

शिक्षा पहले : नांदेड़ में 10 दिन के शिशु के साथ 12वीं की परीक्षा शामिल होने पहुंची महिला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नांदेड़ (महाराष्ट्र)/भाषा। नांदेड़ शहर में एक महिला अपने 10 दिन के बच्चे को गोद में लेकर महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा में शामिल होने पहुंची। इसके बाद अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पर महिला के लिए विशेष इंतजाम किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

शीतल चंद्रकांत चित्ते (21) बुधवार को अपने नवजात शिशु के साथ राजनीति विज्ञान की परीक्षा में शामिल होने केंद्र पर पहुंचीं। इससे पहले प्रसव के महज दो दिन बाद उन्होंने 10 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा में भी बैठी थी। महिला अपनी बहन के साथ अंग्रेजी की परीक्षा में शामिल होने आई थी। शिक्षा के प्रति महिला के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए पीपुल्स कॉलेज के अधिकारियों ने एक समर्पित 'मातृस्नेह कक्षा' (मां के अनुकूल कमरा) बनाया और बच्चे के लिए एक पालने की व्यवस्था की, जिससे शीतल के लिए परीक्षापत्र लिखना आसान हो गया। शीतल की शादी दो साल पहले हुई थी। वह यहां के श्री बसवेश्वर कॉलेज की छात्रा हैं। उन्होंने कहा कि घर पर बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनके पति दिन में काम पर चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि 12 वीं की परीक्षा उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी कारण उन्होंने इसे नहीं छोड़ने का फैसला किया और उनका परिवार भी शिक्षा जारी रखने के उनके फैसले का समर्थन करता है।

नांदेड़ के शिक्षा अधिकारी माधव सालगर ने परीक्षा के दौरान छात्रा के लिए अलग से सुविधा उपलब्ध कराने के कॉलेज के कदम की सराहना की। उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''अब से, हम प्रशासन की ओर से ऐसे छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था करेंगे।'' महाराष्ट्र बोर्ड के लातूर मंडल अध्यक्ष सुधाकर तेलंग ने दावा किया कि राज्य में यह अपनी तरह की पहली पहल है। महाराष्ट्र बोर्ड के तहत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हुईं और केंद्र पर सुचारू रूप से आयोजित हो रही हैं, जहां 861 उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं।

कांग्रेस ने एआई पर प्रधानमंत्री के 'मानव' दृष्टिकोण को लेकर कटाक्ष किया

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कृत्रिम मेधा (एआई) का 'मानव' दृष्टिकोण सामने रखे जाने के बाद बृहस्पतिवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह 'एक्रोनिम इन्फेक्शन' है जिसका कोई इलाज नहीं है।

रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''प्रधानमंत्री ने एआई के लिए अपने 'मानव' दृष्टिकोण का खुलासा किया। इस 'एक्रोनिम इन्फेक्शन' (शब्दों को संक्षिप्त रूप से कहने का संक्रमण) का कोई इलाज नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एआई के लिए एक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया और इसे 'मानव' नाम दिया, जिसमें 'एम' का अर्थ 'मोरल एंड इथिकल सिस्टम्स' (नैतिक एवं नीतिपरक प्रणालियां), 'ए' से तात्पर्य 'अकाउंटेबल गर्वनेंस' (जवाबदेह शासन), 'एन' से तात्पर्य 'नेशनल सॉवेरिनिटी' (राष्ट्रीय संप्रभुता), 'ए' से तात्पर्य 'एक्सेसबल इंड इन्क्लूसिव' (सुलभ और समावेशी) और 'वी' से तात्पर्य 'वैलिड एंड लेजिटिमेट' (वैध और कानूनी) है। उन्होंने कहा, ''हमारे पास प्रतिभा भी है। हमारे पास ऊर्जा क्षमता और नीतिगत स्पष्टता भी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत की तीन कंपनियों ने अपने एआई मॉडल और ऐप्लिकेशन पेश किए हैं। ये मॉडल हमारे युवाओं की प्रतिभा को दर्शाते हैं।

असम के लोगों का राज्य के संसाधनों पर अधिकार है, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का : नवीन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि असम के संसाधनों पर अधिकार केवल असम की जनता का है, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का।

नवीन ने डिब्रूगढ़ जिले के मनोहरी चाय बागान में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए घुसपैठियों के खिलाफ उचित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, ''घुसपैठियों को वापस भेजने संबंधी मुख्यमंत्री की कार्रवाई से पता चलता है कि वह राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्वोत्तर को प्राथमिकता देते हैं और इस क्षेत्र में ''प्रत्येक परियोजना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं''।

उन्होंने दावा किया, ''पिछली केंद्र सरकारों ने भी इस क्षेत्र के लिए धनराशि आवंटित की थी, लेकिन उसका उचित इस्तेमाल नहीं हुआ।'' उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के इस दौर में भी, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई नीतियों के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है।

गावस्कर की अभिषेक को सलाह, पारी के शुरू में 'एक्रॉस द लाइन' शॉट खेलने से बचें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का मानना है कि अभिषेक शर्मा मौजूदा टी20 विश्व कप में उम्मीदों के दबाव से जूझ रहे हैं और वह चाहते हैं कि यह आक्रामक सलामी बल्लेबाज अपनी पारी की शुरुआत में 'एक्रॉस द लाइन' शॉट खेलने से बचे। अभिषेक ने टूर्नामेंट में अभी तक जो तीन मैच खेले हैं उनमें वह खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ वह शुरू में ही आउट हो गए थे।

गावस्कर ने स्टार स्पोर्टस से कहा,''अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन पर उम्मीदों का बोझ साफ दिख रहा है। अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की होती तो बात कुछ और होती। अब बड़े छक्के लगाने वाला शीर्ष बल्लेबाज होने का दबाव उन पर साफ दिख रहा है।'' उन्होंने कहा, ''अपनी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए उन्हें क्रीज पर समय बिताना होगा। उन्हें अपनी पारी की पहली ही गेंद पर चौका या छक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर बड़े शॉट खेलने का मन करे तो ठीक है। लेकिन उन्हें 'एक्रॉस द लाइन' शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।''

गावस्कर ने कहा कि इस 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज को अपनी पारी की शुरुआत में समझदारी से क्रिकेट खेलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''एक रन लो और अपना खाता खोलो। चार डॉट बॉल भी मायने नहीं रखतीं। वह बाद में उनकी भरपाई कर सकता है। उसे शुरुआत में समझदारी से खेलना होगा। एक-दो ओवर क्रीज पर पांव जमाने में बिताओ, फिर अपना स्वाभाविक खेल खेलो।''

भारत ने बुधवार को शिवम दुबे की 31 गेंदों पर खेली गई 66 रन की पारी और वरुण चक्रवर्ती के 14 रन देकर तीन विकेट की बदौलत नीदरलैंड को 17 रन से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया।

गावस्कर ने दुबे की जमकर तारीफ की और कहा कि बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर को अपने खेल में सिर्फ एक शॉट जोड़ने की जरूरत है, जिससे वह बेहद खतरनाक बल्लेबाज बन जाएगा। उन्होंने कहा, ''शिवम दुबे को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास कई तरह के शॉट खेलने की क्षमता है। आप उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट लगाने की क्षमता है। वह सिर्फ मिड-विकेट और स्क्वायर-लेग के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश नहीं करते। वह लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी शॉट लगा सकते हैं।''

3 लाख रु. के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण के साथ बिहार 'नक्सल मुक्त': पुलिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार पुलिस ने दावा किया है कि तीन लाख रुपए के इनामी शीर्ष माओवादी सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम के आत्मसमर्पण के साथ राज्य 'नक्सल मुक्त' हो गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार देर रात जारी एक बयान के अनुसार, कोड़ा पर कम से कम 60 मामले दर्ज थे, जिनमें से कई गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किए गए थे।

बयान में कहा गया है कि कोड़ा ने तीन असॉल्ट राइफल, सैकड़ों कारतूस और मैगजीन के अलावा कुछ नकदी के साथ बुधवार को मुंगेर जिले में विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए संचालित 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना' के तहत कोड़ा को भी लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

सुविचार

जिंदगी में पछतावा नहीं सबक होते हैं, अगर सबक ना लें तो यह पछतावा बन जाते हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

क्या यह विकास नहीं है?

आईआईएम लखनऊ की केस स्टडी 'अयोध्या का आर्थिक पुनर्जागरण' से एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि देश के विकास में मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। यह स्टडी उन कथित बुद्धिजीवियों को भी एक जवाब है, जो कहते थे/हैं- 'मंदिर बन जाने से क्या हो जाएगा ... क्या इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा ... क्या लोगों को रोटी मिल जाएगी ... बीमार लोगों को इलाज मिल जाएगा?' अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनने के बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। अयोध्या के विकास से उत्तर प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिला है। प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के विराजमान होने के बाद एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। पर्यटन आधारित गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि कर राजस्व 20 हजार करोड़ से 25 हजार करोड़ तक होने का अनुमान है। अयोध्या में लगभग 6,000 नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शुरू हुए हैं। क्या यह विकास नहीं है? क्या इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई है? देश में हिंदू आस्था और मंदिरों के बारे में अनर्गल बयान देने का फैशन चल पड़ा था। जो खुद को प्रगतिशील, ज्ञानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति प्रचारित करना चाहता था, वह मीडिया के सामने आकर ये शब्द बोल देता था- 'मंदिर बन जाने से क्या हो जाएगा?' आस्था का उपहास उड़ाना आसान है। इसमें न मेहनत लगती है, न संसाधन खर्च होते हैं। हां, आस्था रखने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलना होता है। हमारे पूर्वजों ने विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष किया था। सदियों तक प्रतीक्षा की थी। कानूनी लड़ाइयां लड़ी थीं। उसके बाद श्रीराम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

प्रभु श्रीराम की कृपा ही है कि जो लोग पहले मंदिर बनाने का विरोध करते थे, अब उसके कारण हो रहे आर्थिक विकास का लाभ उन्हें भी कहीं-न-कहीं मिल रहा है। यह तो शुरुआत है। अगले चार-पांच वर्षों में श्रीराम मंदिर के कारण पर्यटन, परिवहन, आतिथ्य क्षेत्र में सवा लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्या यह बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बात नहीं है? मंदिरों और तीर्थों के कारण देशभर में लाखों परिवारों की रोजी-रोटी चल रही है। श्रीराम मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम थी। छोटे दुकानदार रोजाना बमुश्किल 500 रुपए कमा पाते थे। अब यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है। अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने अयोध्या आकर भगवान के दर्शन किए हैं। दुकानदारों की दैनिक औसत आय चार-पांच गुणा तक बढ़ गई है। क्या दुनिया में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है, जो इतने बड़े स्तर पर लोगों का कल्याण कर सके? क्या पश्चिमी अर्थशास्त्रियों, जिनके लिखे हर शब्द को यहां अकाट्य सत्य मान लिया जाता है, के पास इससे बेहतर कोई मॉडल है? आज अयोध्या के कारण हर जाति और धर्म के लोग खुशहाल हो रहे हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु श्रीराम के विराजमान होते ही सब पर कृपा बरसने लगी है। अयोध्या ने विकास का एक मॉडल पेश किया है। इसका अध्ययन कर हमारे सभी तीर्थस्थलों का विकास करना चाहिए। आम लोगों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जाएं। इसके साथ ही रामराज्य की स्थापना करनी चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक कलह, जातिगत विद्वेष का उन्मूलन करना चाहिए। भाषावाद एवं क्षेत्रवाद को हमेशा के लिए विदा कर दें। 'हम सब भारतीय हैं', 'हम सब एक हैं' की भावना को मजबूत करें। प्रभु श्रीराम ने एकता का संदेश दिया था। यह सोच जन-जन के हृदय में पैदा होनी चाहिए।

ट्वीटर टॉक

टोंक के गोल डूंगरी क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान हुए हादसे में दो मासूम बच्चों की मृत्यु एवं तीन लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करें।

-सचिन पायलट

स्वराज्य के प्रणेता, अदम्य साहसी एवं भारतीय नौसेना के जनक, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन! शिवाजी महाराज का 'राष्ट्र प्रथम' का संकल्प और स्वाभिमान की चेतना आज के 'नए भारत' के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है।

-भजनलाल शर्मा

महान स्वाधीनता सेनानी, सुविख्यात शिक्षाविद, सामाजिक मूल्यों के सजग प्रहरी आचार्य नरेन्द्र देव की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्रसेवा, सामाजिक समरसता और वैचारिक दृढ़ता से ओतप्रोत उनका जीवन सभी को कर्तव्यपथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है।

-योगी आदित्यनाथ

प्रेरक प्रसंग

सत्य की कसौटी

शिवरात्रि की रात महर्षि दयानंद सरस्वती मंदिर में जागरण कर रहे थे। आधी रात के बाद उन्होंने देखा कि जिस शिवलिंग के सामने लोग श्रद्धा से नतमस्तक थे, उसके पास रखा प्रसाद एक चूहा खा रहा है। यह दृश्य उनके मन में गहरा प्रश्न बन गया-यदि यह वास्तव में सर्वशक्तिमान है, तो स्वयं को एक छोटे जीव से क्यों नहीं बचा सकता? इस घटना ने उनके भीतर सत्य की तीव्र खोज जगा दी। उन्होंने घर और सुविधा छोड़ दी और वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। अनेक साधुओं और पंडितों से मिले, पर जहां अंधविश्वास या दिखावा मिला, वहां उन्होंने निडर होकर प्रश्न उठाए। वे केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करते थे; वे प्रमाण और तर्क की मांग करते थे। एक बार एक सभा में उनसे पूछा गया कि यदि वे परंपराओं पर प्रश्न उठाते हैं, तो समाज में अशांति नहीं फैलेगी? दयानंद ने उत्तर दिया कि अशांति प्रश्नों से नहीं, बल्कि असत्य से चिपके रहने से फैलती है। सत्य कभी समाज को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया, पर उसका अर्थ कर्मकांड नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और एकेश्वरवाद था।

सामयिक

रोबोडॉग से परे : भारतीय उच्च शिक्षा का खोखलापन

डॉ. प्रियंका सौरभ

मोबाइल : 7015375570

गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रोबोडॉग के प्रदर्शन से जुड़ा हालिया विवाद सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बना। सतह पर यह मामला उपयुक्तता, प्राथमिकताओं या कैंपस संस्कृति से जुड़ा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से पनप रहे एक गहरे और संरचनात्मक संकट का केवल एक लक्षण है। समस्या रोबोडॉग नहीं है। समस्या यह है कि हमारे विश्वविद्यालय धीरे-धीरे क्या बनते चले गए हैं। पिछले दो दशकों में भारत में उच्च शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। निजी विश्वविद्यालयों, स्ववित्तपोषित कॉलेजों और डिग्री संस्थानों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इस विस्तार को अक्सर शिक्षा तक पहुँच बढ़ने और जनसांख्यिकीय लाभ के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब यह विस्तार समानांतर नियमन, अकादमिक कठोरता और जवाबदेही के बिना हुआ, तो इसकी क़ीमत गुणवत्ता को चुकानी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि मात्रा बढ़ी, पर गुणवत्ता लगातार गिरती चली गई। आज देश के अधिकांश-हालाँकि सभी नहीं-निजी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज शिक्षा के केंद्र कम और डिग्री वितरण केंद्र अधिक बन गए हैं। शिक्षा एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लेन-देन बनती जा रही है-पैसे के बदले डिग्री। उपस्थिति, अकादमिक भागीदारी, प्रयोगशाला कार्य और बौद्धिक अनुशासन जैसी बातें अब अनिवार्य नहीं रहीं, बल्कि समझौते के दायरे में आ गई हैं। जो कभी उच्च शिक्षा में गैर-समझौतावादी हुआ करता था, वह अब लचीला, कमजोर और विकृत हो चुका है।

यह गिरावट विशेष रूप से उन विषयों में चिंताजनक है जहाँ कठोरता अनिवार्य है। सैद्धांतिक पढ़ाई का कमजोर होना एक बात है, लेकिन विज्ञान शिक्षा का खोखला हो जाना कहीं अधिक गंभीर है। आज स्थिति यह है कि छात्र बिना नियमित कक्षाओं में गए और बिना प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण लिए विज्ञान जैसे विषयों में स्नातक और परास्नातक डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं। प्रयोगात्मक कार्य-जो कभी वैज्ञानिक प्रशिक्षण की रीढ़ हुआ करता था-अब औपचारिकता बनकर रह गया है। डिग्रियाँ तो दी जा रही हैं, लेकिन दक्षता सुनिश्चित नहीं की जा रही। इस खोखलेपन के परिणाम तब स्पष्ट होते हैं जब छात्र नौकरी के लिए सामने आते हैं। रसायन विज्ञान में परास्नातक छात्र बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाएँ नहीं समझा पाता। कॉमर्स स्नातक डेबिट और क्रेडिट की मूल अवधारणा स्पष्ट नहीं कर पाता। प्रबंधन की डिग्री रखने वाला छात्र समस्या-समाधान और आलोचनात्मक सोच में कमजोर दिखाई देता है। ये कोई इक्का-दुक्का उदाहरण नहीं, बल्कि उद्योग जगत द्वारा बार-बार देखी जा रही सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं।

स्वाभाविक रूप से इससे छात्रों और अभिभावकों में निराशा पैदा होती है। वर्षों की पढ़ाई और भारी आर्थिक निवेश के बावजूद जब रोजगार नहीं मिलता, तो सवाल उठते हैं। माता-पिता यह पूछने में बिल्कुल सही होते हैं कि पढ़ाई के बाद भी बच्चा बेरोज़गार क्यों है। अक्सर इस असंतोष का निशाना सरकार बनती है, जिस पर रोजगार सृजन न कर पाने का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि रोजगार सृजन एक नीतिगत चुनौती है, लेकिन यह विमर्श एक असहज सच्चाई को नज़रअंदाज़ कर देता है-कि बड़ी संख्या में स्नातक वास्तव में रोजगार-योग्य ही नहीं हैं। यहीं से मूल प्रश्न जन्म लेता है। यदि छात्रों में आवश्यक ज्ञान और कौशल नहीं है, तो उन्हें योग्य घोषित करने वाली डिग्रियाँ उन्हें कैसे मिल गईं? ऐसी संस्थाओं को बिना अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित किए प्रमाणपत्र बाँटने की अनुमति किसने दी? इसका उत्तर हमें उच्च शिक्षा के नियामक ढाँचे में मिलता है। भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख कई मंत्रालयों, विभागों और नियामक संस्थाओं द्वारा की जाती है, जिनका घोषित उद्देश्य मानकों की रक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अकादमिक ईमानदारी बनाए रखना है। मान्यता प्रणालियाँ, निरीक्षण, मूल्यांकन और अकादमिक ऑडिट इसी उद्देश्य से बनाए गए थे। लेकिन व्यवहार में ये प्रक्रियाएँ अक्सर वास्तविक मूल्यांकन की बजाय औपचारिक अनुष्ठान बनकर रह गई हैं।

निरीक्षण प्रायः पूर्व-निर्धारित होते हैं। दस्तावेज़ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सजाए जाते हैं। इमारतों और बुनियादी ढाँचे को शिक्षण गुणवत्ता पर प्राथमिकता दी जाती है। अनुपालन को सीखने के परिणामों से ऊपर रखा जाता है। छात्रों का वास्तविक अकादमिक अनुभव, शिक्षण की गुणवत्ता, परीक्षा की कठोरता और जिज्ञासा की संस्कृति-इन पर गंभीर और निरंतर निगरानी शायद ही होती है। नतीजतन, संस्थान शिक्षा सुधारने के बजाय नियामकों को मैनेज करना सीख लेते हैं। इस नियामक शिथिलता ने एक दुष्चक्र को जन्म दिया है-संस्थान न्यूनतम अकादमिक जवाबदेही के साथ चलते रहते हैं, नियामक निगरानी का आभास बनाए रखते हैं, और डिग्रियाँ लगातार जारी होती रहती हैं। इस व्यवस्था की क़ीमत न तो संस्थान चुकाते हैं, न ही नियामक-बल्कि छात्र, नियोक्ता और समाज चुकाता है।

विडंबना यह है कि एक ओर उद्योग जगत योग्य मानव संसाधन की कमी की शिकायत करता है, वहीं दूसरी ओर देश शिक्षित बेरोज़गारी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है जहाँ प्रमाणपत्र को क्षमता से ऊपर रखा गया है। कंपनियाँ नए कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने पर भारी ख़र्च करने को मजबूर हैं, जबकि युवा पेशेवर आत्मविश्वास की कमी और करियर ठहराव से जूझते हैं। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार वे ईमानदार और प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो अक्सर विकल्पों की कमी या भ्रामक ब्रांडिंग के कारण औसत संस्थानों में दाख़िला ले लेते हैं। वे मेहनत करते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपनी काबिलियत से ज़्यादा अपनी मार्कशीट पर दर्ज संस्थान के नाम का बोझ उठाना पड़ता है। उनकी व्यक्तिगत योग्यता संस्थागत विश्वसनीयता की कमी में दब जाती है। यह केवल अन्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की बर्बादी है।

यह स्वीकार करना होगा कि भारत में आज भी कुछ उच्च-गुणवत्ता वाले संस्थान मौजूद हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन वे अपवाद हैं, नियम नहीं। उल्लेखनीय है कि बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा आज भी अपेक्षाकृत अधिक संरचित और नियंत्रित है। जैसे ही छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, निगरानी ढीली पड़ जाती है और अपेक्षाएँ धुंधली हो जाती हैं। यदि इस प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम गंभीर होंगे। डिग्रियों का सामाजिक और आर्थिक मूल्य घटेगा। उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक विश्वास कमजोर होगा। योग्यता और औसतपन के बीच का अंतर और अधिक अस्पष्ट होता जाएगा। हर गली में विश्वविद्यालय जैसे वाक्य व्यंग्य नहीं, बल्कि यथार्थ का वर्णन बन जाएंगे-जहाँ विश्वविद्यालय तो हर जगह होंगे, पर शिक्षा नहीं। अब सुधार का समय है-और वह सुधार ईमानदार और कठोर होना चाहिए। नियामक संस्थाओं को बॉक्स-टिकिंग से आगे जाकर परिणाम-आधारित, पारदर्शी और अप्रत्याशित मूल्यांकन अपनाना होगा। शिक्षण की गुणवत्ता, सीखने के परिणाम, छात्र सहभागिता और मूल्यांकन की ईमानदारी को इमारतों और विज्ञापनों से ऊपर रखना होगा।

संस्थानों की जवाबदेही तय करनी होगी। जो कॉलेज और विश्वविद्यालय लगातार अकादमिक रूप से असफल हो रहे हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए-सीटों में कटौती, पाठ्यक्रम निलंबन या मान्यता रद्द करने तक। उच्च शिक्षा ऐसा व्यवसाय नहीं हो सकता जहाँ असफलता की कोई क़ीमत न चुकानी पड़े। छात्रों और अभिभावकों को भी अधिक सजग होना होगा। केवल मार्केटिंग, बुनियादी ढाँचे और ब्रांडिंग के आधार पर निर्णय लेना भविष्य के साथ समझौता है। शिक्षा कोई साधारण ख़रीद नहीं, बल्कि बौद्धिक और व्यावसायिक विकास में निवेश है-और ग़लत निर्णयों के दूरगामी परिणाम होते हैं। अंततः, उच्च शिक्षा का उद्देश्य डिग्री बाँटना नहीं, बल्कि सोचने-समझने वाले, सक्षम और ज़िम्मेदार नागरिक तैयार करना है। जब तक यह मूल उद्देश्य पुनः स्थापित नहीं होता, तब तक रोबोडॉग जैसे विवाद आते रहेंगे-कुछ समय के लिए शोर मचाएँगे और फिर शांत हो जाएँगे-जबकि असली संकट जस का तस बना रहेगा। हमें सजावटी सुधार नहीं, बल्कि प्रणालीगत आत्ममंथन चाहिए। क्योंकि शिक्षा का संकट कभी केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता-वह चुपचाप राष्ट्र का भविष्य गढ़ता है।

चिंतन

जब तक अंतिम व्यक्ति सुरक्षित नहीं, अधूरा है विकास

योगेश कुमार गोयल

मोबाइल : 9416740584.

किसी भी समाज की सच्ची प्रगति उसकी ऊंची इमारतों या तेज आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह अपने सबसे कमजोर, वंचित और हाशिए पर खड़े नागरिकों को कितना न्यायपूर्ण, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। 20 फरवरी को मनाया जाने वाला सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मानव सभ्यता की उस मूल चेतना का प्रतीक है, जिसके बिना न तो शांति संभव है और न ही टिकाऊ विकास। इस दिवस की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, असमानता और भेदभाव जैसी जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए देशों के बीच साझा प्रतिबद्धता को मजबूती मिल सके। यह एक चेतावनी भी है कि बढ़ती असमानताएं समाज की नींव को भीतर से कमजोर कर रही हैं और साथ ही एक अवसर भी है कि समय रहते ठोस नीतियों, संवेदनशील शासन और सामूहिक प्रयासों से इस प्रवृत्ति को बदला जा सकता है।

वर्ष 2026 में सामाजिक न्याय का विश्व दिवस की थीम है 'समावेशन को सशक्त बनाना: सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना'। यह थीम स्पष्ट करती है कि असमानताओं को कम करने के लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि विकास की प्रक्रिया में समाज के हर वर्ग की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो। समावेशन का अर्थ केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उन लोगों की आवाज को स्थान देना है, जो अब तक हाशिए पर रहे हैं। जब तक नीतियां केवल केंद्रों में बनती रहेंगी और उनका प्रभाव जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक सामाजिक न्याय एक अधूरा लक्ष्य बना रहेगा। यह दिवस विशेष प्रासंगिकता रखता है क्योंकि आज की दुनिया एक गहरे संक्रमणकाल से गुजर रही है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक तनावों ने आर्थिक व सामाजिक ढ़ांचों को तेजी से बदला है। इन बदलावों का लाभ जहां कुछ सीमित वर्गों तक सिमट गया है, वहीं बड़ी आबादी, विशेषकर गरीब, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, महिलाएं, प्रवासी, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक समुदाय, और अधिक असुरक्षित होती जा रही है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय केवल नैतिक आदर्श नहीं, नीति और शासन की अनिवार्य प्राथमिकता बन चुका है।

भारत में सामाजिक न्याय का विचार गहरे संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा है। संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है जबकि मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत असमानताओं को कम करने और कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से आरक्षण नीति, सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश तथा कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बावजूद इसके, क्षेत्रीय असमानताएं, शहरी-ग्रामीण विभाजन, डिजिटल डिवाइड और लैंगिक विषमता जैसी चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं।

सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है कि क्या हमारी नीतियां अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, क्या शिक्षा और रोजगार के अवसर वास्तव में समान हैं, और क्या विकास का लाभ संतुलित रूप से बंट रहा है?

यह दिवस यह भी याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी एक देश या सरकार की नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग और सामूहिक प्रयास की मांग करती है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस 2026 इस सत्य को दोहराता है कि सच्ची प्रगति तभी संभव है, जब कोई भी पीछे न छूटे। समावेशन और सशक्तिकरण केवल शब्द नहीं बल्कि रोजमर्रा के निर्णयों, नीतियों और सामाजिक व्यवहारों में उतारने योग्य जिम्मेदारी हैं। जब हर व्यक्ति को समान गरिमा, अवसर और सुरक्षा मिलती है, तभी न्याय कागजों से निकलकर जीवन की वास्तविकता बनता है और एक अधिक मानवीय, समावेशी तथा न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण संभव हो पाता है।

नजरिया

मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम प्रहार

बाल मुकुंद ओझा

मोबाइल : 9414441218

फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि घाटे में चल रहे राज्य मुफ्त भोजन, बिजली और साइकिल जैसी योजनाएं बांट रहे हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणियां तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम बनाम केंद्र सरकार मामले की सुनवाई के दौरान की है। सीजेआई ने कहा कि राज्य को रोजगार के अवसर खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से ही मुफ्त भोजन देना शुरू कर दें, फिर मुफ्त साइकिल, फिर मुफ्त बिजली और अब हम उस स्थिति तक पहुंच रहे हैं, जहां हम सीधे लोगों के खातों में नकद राशि स्थानांतरित कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि फ्रीबीज की फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। हम केवल तमिलनाडु के संदर्भ में ही बात नहीं कर रहे हैं। हम इस तथ्य पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले योजनाएं क्यों घोषित की जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों समाजशास्त्रियों को अपनी विचारधारा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर चुनावों के दौरान मुफ्त की रेवड़ियों पर कड़ा प्रहार किया है। चुनावों के दौरान सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे और प्रतिवादे करती है। सरकार बनने के बाद चुनावी वादे पूरा करने में पार्टियों के पसीने छुट जाते है। कई राज्यों की अर्थव्यवस्था तो चौपट तक हो जाती है जिसके कारण सम्बध सरकारों को अपने कर्मचारियों के वेतन आदि चुकाने के लाले पड़ जाते है। राजनैतिक पार्टियों द्वारा मत हासिल करने के लिए राजकीय कोष से मुफ्त सुविधाएं देने का प्रकरण सियासी हलकों में गर्माने लगा है। देश की प्रबुद्ध जमात का मानना है इससे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हिलने लगी है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान इस तरह के वादे करने का चलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

देखा गया है चुनावों में सभी दल लोकलुभावन वादों के जरिए दूसरे दलों से आगे निकलने की जुगत में हैं। आम आदमी पार्टी मुफ्त सुविधाएं देने के वादों में सबसे आगे है। यह पार्टी मतदाताओं को मुफ्त बिजली पानी आदि लुभावनी घोषणाएं कर दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल कर चुकी है। जिन्हें मुफ्त की योजनाएं मिल रही हैं वो कहते हैं कि फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर सही है, लेकिन जो टैक्सपेयर हैं और जिनकी कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स में जाता है वो इसे गलत बताते हैं। पिछले अनेक चुनावों में मुफ्त उपहार और सुविधाएं देने की एक परंपरा सी पड़ गई। मतदाता भी ऐसी घोषणाओं का इंतज़ार करते है जो किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के हितकारी नहीं कहा जा सकता। बताते है चुनावी लोकतंत्र में मुफ्त उपहार की परंपरा तमिलनाडु से शुरू हुई थी। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की नेत्री जय ललिता ने मुफ्त उपहार बाँट कर द्रमुक से सत्ता छीनी थी। वहां पहले मोबाइल, टीवी सेट, डिनर सेट, हैदराबादी मोती के सेट बंट चुके हैं। पिछले अनेक चुनावों में मुफ्त उपहार और सुविधाएं देने की एक परंपरा सी पड़ गई। मतदाता भी ऐसी घोषणाओं का इंतज़ार करते है जो किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के हितकारी नहीं कहा जा सकता।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

युवाओं में बढ़ते आक्रोश से एक और जनविद्रोह की आग भड़क सकती है : कार्की

काठमांडू/भाषा

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि अगर युवाओं के असंतोष का समाधान नहीं किया गया तो इससे एक और विद्रोह की आग भड़क सकती है।

काठमांडू में नेपाली सेना पवेलियन में 76वें लोकतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ठोस परिणाम देने वाला होना चाहिए, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।

पिछले साल सितंबर में 'जेनरेशन जेड' (जेन-जेड) के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कार्की ने कहा, उस आंदोलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और भेदभाव को समाप्त करना था। इसका उद्देश्य सुशासन और समान न्याय सुनिश्चित करना था।

नेपाल में युवाओं के इस प्रदर्शन के कारण के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था।

उन्होंने आगे कहा, राज्य को न केवल उदारता से, बल्कि विनम्रता और कर्तव्य की गहरी भावना से भी इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं की असंतोष की समस्या का समाधान नहीं करने से एक और विद्रोह भड़क सकता है।

पिछले साल 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं कार्की ने कहा, युवाओं को कमजोर करके कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, युवाओं में ऊर्जा, बदलाव की आकांक्षा और आक्रोश है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र न केवल एक प्रक्रिया है, बल्कि एक परिणामोन्मुखी प्रणाली है। उन्होंने कहा, हमने सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन व्यवहार में हमने भेदभाव को बढ़ावा देना जारी रखा। हमने संविधान में समानता का प्रावधान किया; फिर भी अपनी व्यवस्थाओं के भीतर हम असमानता को प्रश्रय देते रहे।

कार्की ने कहा कि सत्ता और संसाधनों पर एकाधिकार ने जनता के विश्वास को कम कर दिया है, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला है।

इसके अलावा, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कामना व्यक्त की कि लोकतंत्र दिवस देश में स्थायी शांति, सुशासन, विकास और समृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो।

राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि नेपाली लोगों को 1950 की क्रांति को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण आधार थी।

नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1950 की क्रांति के माध्यम से हुई, जिसने राणा प्रधानमंत्रियों के 104 साल पुराने वंशानुगत शासन को समाप्त कर दिया और राजा को नाममात्र का प्रमुख बना दिया।

होली

मुरादाबाद में होली से पहले एक बाज़ार में जानवरों के मास्क पहने लोग और पानी की बंदूकें पकड़े हुए।

जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव बोले- 'न्यायालय के फैसले का सम्मान करूंगा'

सहारनपुर/एजेन्सी

जेल से रिहा होने के बाद मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव अपने पैतृक घर पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएनएस के साथ खास बातचीत की और सभी का आभार व्यक्त किया। अभिनेता ने कहा, अभी मैं मंगलवार को अपने घर पहुंचा और घर में फंक्शन चल रहे हैं। ये कार्यक्रम गुरुवार-शुक्रवार तक चलेंगे। इसके बाद मैं फिर से मीडिया से विस्तार से बात करूंगा। अभिनेता ने स्पष्ट करते हुए बताया कि केस से जुड़ी सभी कानूनी कार्रवाई उनके वकील भास्कर उपाध्याय सही से बताएंगे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा न्यायालय की शरण में रहा हूं और आगे भी रहूंगा। हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगा, उसका पूरी तरह पालन करूंगा।उन्होंने आगे बताया कि वे जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने सभी समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आईएएनएस के जरिए पूरे देश-दुनिया, सिनेमा जगत और आम लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया या अन्य तरीकों से मेरा साथ दिया, आशीर्वाद दिया और मदद की, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं।राजपाल यादव ने आगे जोर देते हुए कहा, मुझे हमेशा विश्वास था कि पूरा देश, भारतीय सिनेमा, और लाखों लोग मेरे साथ हैं। यह साथ जीवन भर रहेगा। भारतीय सिनेमा मेरी कर्मभूमि है। इसी के माध्यम से मुझे दुनिया भर में काम करने का मौका मिला। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने मेरा साथ दिया।

'अस्सी' सिर्फ एक फिल्म नहीं, कड़वा सच है : श्रीलेखा मित्रा

कोलकाता/एजेन्सी

मशहूर निर्देशक अनुभव सिन्हा ने एक बार फिर फिल्म 'अस्सी' के जरिए महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को उजागर किया है। हाल ही में फिल्म का प्रीमियर कोलकाता में रखा गया था, जहां पर अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि यह फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और समाज की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। उन्होंने कहा, फिल्म का नाम 'अस्सी' इसलिए रखा गया है क्योंकि कहानी में जिस दिन लड़की के साथ अत्याचार हुआ था, उसी दिन 80 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था। फिल्म में भी सवाल उठाया गया है कि अगर एक दिन में 80 घटनाएं होती हैं, तो पूरे साल कितनी घटनाएं होंगी? उन्होंने आगे कहा, यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा

समाज सच में आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है, या बीच में ही ठहर गया है। आखिर में हम जा कहां रहे हैं? यह फिल्म बहुत विचारोत्तेजक है। यह हमारे सिस्टम पर सवाल उठाती है कि यह सब कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म होगा, और बीच में क्या हो रहा है। अभिनेत्री ने 'एपस्टीन फाइल्स' का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, अभी हाल ही में 'एपस्टीन फाइल्स' आई, जिसमें उन लोगों के नाम सामने आए, जिनका नाम हम सम्मान और इज्जत के साथ लेते हैं। दुनियाभर में पावरफुल और नामी लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। पावर और पैसे के साथ बुराई का गहरा रिश्ता है। यह फिल्म भी उसी तरह सोचने पर मजबूर करती है। अभिनेत्री ने कहा, हमारे यहां डॉक्टर और इंजीनियर लाइन में खड़े हैं। डॉक्टर और शिक्षक भी मजबूरी में हैं। हमारे पास एक महान देश और महान राज्य है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सोचना पड़ता है कि हम कहां पहुंच गए हैं।

'द वार्डरोब' का रहस्यों से भरा पोस्टर जारी

नई दिल्ली/एजेन्सी

राज गवाली प्रोडक्शन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वार्डरोब' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है। सौरभ चौबे के निर्देशन में तैयार इस सुपरनैचुरल थ्रिलर-हॉरर फिल्म में दिव्या अग्रवाल और रजनीश दुग्गल मुख्य भूमिकाओं में हैं। 'द वॉर्डरोब' के पोस्टर में डरावना और रहस्यमयी माहौल साफ झलकता है, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। फर्स्ट लुक पोस्टर में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई गई है, जो आधी खुली हुई है। अलमारी पर बेलें लिपटी हुई हैं और अंदर से लाल रोशनी निकल रही है। खून से सनी सफेद पोशाक पहने एक रहस्यमयी महिला की आकृति बाहर झांकती नजर आ रही है। धुंधला और छायादार बैकग्राउंड सुपरनैचुरल टोन को और गहरा करता दिख रहा है। पोस्टर के नीचे फिल्म का टाइटल गहरे लाल रंग में लिखा है, जो हॉरर थीम को मजबूती देता है। साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 24 अप्रैल भी घोषित कर दी है। फिल्म में दिव्या अग्रवाल रजनीश के साथ लीड रोल में हैं। वह पहले बिग बॉस ओटीटी और एमटीवी एस ऑफ स्पेस की विजेता रह चुकी हैं।

दिव्या ने कहा, यह फिल्म मेरे लिए एक्टर के तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण रही। कहानी बेहद रोमांचक और रहस्य से भरी है। मैं चाहती हूं कि दर्शक इसे थिएटर में बड़े पर्दे पर देखें और महसूस करें।

अभिनेता रजनीश दुग्गल ने स्क्रिप्ट की तारीफ करते हुए कहा, जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, लगा कि इसमें कुछ अलग और खास है। यह सस्पेंस, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स और सुपरनैचुरल का अनोखा मिश्रण है। पोस्टर सिर्फ एक झलक है, पूरी कहानी और भी दिलचस्प है।निर्माता ज्योति राज गवाली ने बताया, द वार्डरोब सिर्फ डराने वाली फिल्म नहीं है। यह उन रहस्यों की कहानी है जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। हम चाहते थे कि फर्स्ट लुक पोस्टर से ही इसकी इंटेंसिटी और रहस्य की झलक मिले। सह-निर्माता राज गवाली के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। फिल्म की कहानी एक पुरानी अलमारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें छिपे राज दर्शकों को सस्पेंस में रखेंगे। निर्माताओं का कहना है कि जल्द ही ट्रेलर, गाने और अन्य जानकारी साझा की जाएगी।

रोहित शेट्टी फायरिंग केस : हरियाणा से हथियार बरामद, बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेजी गई पिस्तौल

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान वह हथियार बरामद कर लिया गया है, जिसका इस्तेमाल शूटर ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के लिए किया था। यह पिस्तौल हरियाणा से बरामद की गई, जिसे अब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री भेज दिया गया है। लैबोरेट्री में हथियार का बैलिस्टिक टेस्ट कराया जाएगा, ताकि वैज्ञानिक रूप से यह पुष्टि हो सके कि यही हथियार फायरिंग की वारदात में इस्तेमाल हुआ था। क्राइम ब्रांच के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम हरियाणा गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल वहीं छिपा रखी थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार बरामद किया। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद केस की कड़ियां और मजबूत होंगी।इस बरामदगी के बाद अब पूरा मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस के अनुसार, बिश्नोई गैंग के शुभम लोनकर और उसके भाई प्रवीण लोनकर ने मिलकर फायरिंग की योजना बनाई थी।

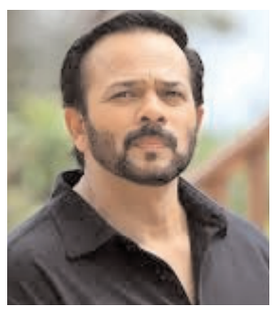

खास बात यह है कि प्रवीण लोनकर इस वक्त बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जेल में बंद है। इसके बावजूद उस पर आरोप है कि उसने जेल से ही इस साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई।पुलिस को शक है कि प्रवीण लोनकर ने जेल में रहते हुए अपने नेटवर्क के जरिए शूटरों को हथियार, मोटरसाइकिल और फायरिंग के लिए जरूरी रकम उपलब्ध कराई। उसने पूरे ऑपरेशन को रिमोट कंट्रोल की तरह जेल से संचालित किया। इस मामले में अब तक पुणे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच की करीब 12 टीमें इस केस की जांच में लगी हुई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, प्रवीण लोनकर को जल्द ही इस फायरिंग केस में औपचारिक रूप से पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा।

प्यार या परिवार? 'संगमरमर' के ट्रेलर में दिखी बलिदान और भावनाओं की अनोखी दास्तां

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म निर्देशक-निर्माता सूरज बड़जात्या की आगामी वेब सीरीज 'संगमरमर' जल्द ही स्ट्रीम होने वाली है। मल्टी-जेनरेशनल फैमिली ड्रामा सीरीज का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सीरीज में अभिनेता सौरभ जैन और अभिनेत्री सीन सविता दास मुख्य भूमिका में हैं। 1 मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर में इसकी कहानी काफी प्रभावशाली है। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है, जिसका जीवन एक बड़े फैसले से पूरी तरह बदल जाता है। जब अमृता जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है तो वह अपनी निजी खुशियों और आदित्य के साथ बढ़ते प्यार को छोड़कर परिवार की जिम्मेदारियों को चुनती है। ट्रेलर में परिवार, प्यार, समझौते और इंतजार की भावनाएं बहुत गहराई से उभरकर आई हैं। निर्देशक-निर्माता सूरज बड़जात्या ने सीरीज को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'संगमरमर' उन परिवारों की कहानी है, जो हम सबके आसपास होते हैं। यह रिश्तों को बिल्कुल सच्चे और असली रूप में दिखाती है, जिसमें प्यार, गलतफहमियां, इंतजार और एक-दूसरे के साथ बने रहने की कोशिश है। इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा सब्र है। यह बताती है कि समय रिश्तों को कितनी चुनौतियां दे सकता है और उन्हें

कैसे ठीक भी कर सकता है। जियो स्टूडियोज और जियो हॉटस्टार के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम इस कहानी को इतने ईमानदार और सच्चे तरीके से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जैसा हम चाहते थे।

सीरीज का निर्देशन विक्रम घई ने किया है। सीरीज में शीन सविता दास अमृता नाम की लड़की का किरदार निभाया है। उन्होंने अपने किरदार को लेकर बताया, सीरीज की पूरी कहानी अमृता के इर्द-गिर्द घूमती है और कई बड़े फैसले उसके कंधों पर होते हैं। इस किरदार को निभाते हुए मुझे सबसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी चुनने की आदत लगी।

वह अपनी खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी को प्राथमिकता देती है। एक अभिनेत्री के तौर पर मुझे ये संघर्ष बहुत रियल लगा। अमृता के सफर को जीना मेरे लिए व्यक्तिगत अनुभव जैसा था। मुझे उसकी खामोशी, समझौतों और शांत ताकत को महसूस करना पड़ा। सूरज बड़जात्या के साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। उनकी कहानियों ने हम सबका परिवार और रिश्तों को देखने का तरीका बदला है।

वहीं, वसुधा के किरदार में नजर आने वाली स्मिता बंसल ने कहा, वसुधा परिवार की भावनात्मक रीढ़ हैं। वह चुपचाप प्यार और ताकत से सब कुछ संभालती हैं। उनकी मौजूदगी भले ही कम हो, लेकिन अमृता की जिंदगी और फैसलों पर उनका गहरा असर पड़ता है। मुझे 'संगमरमर' में सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह मां के प्यार और मूल्यों के पीढ़ियों तक चलने वाले प्रभाव को दिखाती है। परिवार के रिश्तों और भावनात्मक मजबूती को सेलिब्रेट करने वाली कहानी का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खास रहा।

'कैनेडी' को लेकर सनी लियोनी के दिल में बैठा डर, अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर बड़े नामों से जुड़ा प्रोजेक्ट कलाकारों के लिए एक सपने जैसा होता है। ऐसा ही अनुभव अभिनेत्री सनी लियोनी ने साझा किया। अपनी अपकमिंग स्ट्रीमिंग फिल्म 'कैनेडी' को लेकर सनी लियोनी ने बताया कि इसका हिस्सा बनने पर उन्हें आखिरी दिन तक यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें हमेशा रिप्लेस होने का डर रहा। सनी लियोनी इन दिनों अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी 'कैनेडी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म को 2023 में कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसके अलावा, फिल्म ने कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में सराहना प्राप्त की है। सनी ने कहा, ''जब मुझे इस फिल्म का ऑफर मिला, तो मैं काफी हैरान थी। मुझे भरोसा ही नहीं था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन गई हूं। ट्रायल्स, वर्कशॉप्स और मीटिंग्स सब कुछ होने के बावजूद, मेरे मन में यह डर बना रहा कि कहीं आखिरी समय पर मुझे फिल्म से रिप्लेस न कर दिया जाए।''

उन्होंने कहा, ''एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चीजें पल भर में बदल जाती हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सब कुछ तय होने के बाद भी कलाकार बदल दिए जाते हैं। इसी वजह से मुझे तब तक चैन नहीं मिला, जब तक मैंने सेट पर पहुंचकर कैमरे के सामने शॉट नहीं दिया। पहला सीन शूट होने और फिर

अगला सीन शुरू होने के बाद मुझे यकीन हुआ कि अब शायद उन्हें रिप्लेस नहीं किया जाएगा।'' सनी लियोनी ने कहा, ''पहला शॉट ओके होने के बाद मेरे मन में एक अलग ही सुकून था। मुझे लगा कि मैंने अपना काम ठीक से किया है और शायद यही वजह है कि टीम अब मुझ पर भरोसा कर रही है।''

फिल्म 'कैनेडी' में सनी लियोनी चार्ली नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं। अपने किरदार के एक खास सीन का जिक्र करते हुए सनी ने बताया कि यह सीन एक होटल रूम में शूट हुआ है, जहां मेरा किरदार चार्ली एक पुलिस ऑफिसर का इंतजार करती है। वह डरी हुई है, परेशान है और वहां रहना नहीं चाहती, लेकिन उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। इस सीन में बाथरूम से बाहर आकर चेहरे पर नकली मुस्कान लाना, उनके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा। सनी ने कहा, ''यह सीन आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कई बार हम सब भी ऐसे हालात से गुजरते हैं, जहां अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। यह आसान नहीं होता। यही वजह है कि यह सीन मेरे लिए बेहद खास है।''

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026: एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने एआई क्षेत्र में भारत की ताकत पर जताया गर्व

नई दिल्ली/एजेन्सी

नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो 2026 में मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने एआई क्षेत्र में भारत की ताकत पर गर्व जताया। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। मैं जल्द ही एक सेशन में जाऊंगी और आप सभी के साथ वापस आऊंगी। मैं एआई समिट के लिए एक भारतीय होने के नाते बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं। भूमि ने इस समिट को भारत की तकनीकी प्रगति का एक बड़ा मंच बताया और कहा कि एआई का सही उपयोग समाज के हर वर्ग तक पहुंच सकता है। वे समिट में एआई के सामाजिक प्रभाव और जिम्मेदार इस्तेमाल पर चर्चा करने के लिए शामिल हुईं। समिट में कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के सीईओ

संजीव कुमार गुप्ता ने भी एआई की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि एआई इम्पैक्ट समिट एआई में भारत की काबिलियत की असली ताकत दिखा रहा है और जाहिर है, कर्नाटक राज्य यहां भी एआई की काबिलियत दिखाने में एक लीडिंग राज्य के तौर पर आता है। उन्होंने बताया, हम यहां तीन अलग-अलग चीजों का ध्यान रखने आए हैं। पहला, ई-गवर्नेंस में एआई कैसे अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है, जिसके लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा स्टार्टअप का क्षेत्र है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं, तीसरा कदम एआई का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसके लिए कई देशों के डेलिगेशन आ रहे हैं। कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं। समिट में कर्नाटक ने अपनी एआई पहलों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया है।

बेंगलुरु को भारत का एआई हब कहे जाने के कारण राज्य ने ई-गवर्नेंस, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम में एआई के उपयोग के कई प्रोजेक्ट दिखाए हैं। संजीव गुप्ता ने बताया कि कर्नाटक एआई स्किल डेवलपमेंट, एथिकल एआई गाइडलाइंस और ग्लोबल पार्टनरशिप पर फोकस कर रहा है। समिट में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 300 से अधिक प्रदर्शक और वैश्विक एआई लीडर्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित इस आयोजन में एआई को मानवता, समावेशी विकास और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए आकार देने पर जोर दिया जा रहा है।

आईओबी ने अखिल भारतीय हैकाथॉन के लिए आरएमके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ समझौता किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय साइबर सुरक्षा हैकाथॉन आयोजित करने के लिए तिरुवल्लूर स्थित आरएमके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के देश भर में बैंकिंग क्षेत्र में उद्यमिता और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

आरएमके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करेगा, जो शैक्षणिक सहायता प्रदान करेगा और पूरे भारत से छात्रों की भागीदारी को सुगम बनाएगा। यह प्रतियोगिता कुछ महीनों तक चलेगी, जिसमें भाग लेने वाली विभिन्न कॉलेज टीमों को अकादमिक विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपने विचारों को निखारने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन का समापन मई 2026 में होने की उम्मीद है, जिसमें कार्यान्वयन और उद्यमिता की उच्च क्षमता प्रदर्शित करने वाले विजेता प्रोटोटाइप का चयन किया जाएगा। साथ ही, छात्रों को आगामी ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026 में एक प्रमुख मंच पर अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा।

इस पहल पर बोलते हुए, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा, इंडियन ओवरसीज बैंक में, हम युवा प्रतिभाओं को पोषित करने और भविष्य के लिए अभिनव बैंकिंग समाधान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हैकाथॉन डिजिटल परिवर्तन और फिनटेक क्षेत्र में कौशल विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इसके अलावा, यह समझौता ज्ञापन नवाचार को बढ़ावा देने में शिक्षा जगत और बैंकिंग क्षेत्र के बीच सहयोग को समृद्ध करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पहल न केवल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती है, बल्कि छात्रों को बैंकिंग के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने में भी सक्षम बनाती है, जिससे तकनीकी उन्नति और समावेशी विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने हैम्बर्ग पोर्ट अथॉरिटी के प्रतिनिधियों का किया स्वागत

फ्यूचर-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और एआई पर फोकस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को हैम्बर्ग पोर्ट अथॉरिटी (एचपीए) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का आतिथ्य किया। यह एक ऑफिशियल एंगेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था जिसका मकसद पोर्ट डेवलपमेंट और ऑपरेशन्स में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नॉलेज एक्सचेंज को मजबूत करना था। डेलीगेशन को हैम्बर्ग पोर्ट अथॉरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ मिस्टर जेन्स मायर ने लीड किया, और इसमें पोर्ट ऑफ़ हैम्बर्ग इकोसिस्टम के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, जिसमें टर्मिनल ऑपरेशन्स, लॉजिस्टिक्स, कंसल्टिंग, क्रूज, डिजिटल आइडेंटिटी/एक्सेस सिस्टम्स और एकेडेमिया शामिल थे।

यह दौरा चेन्नई पोर्ट टूर से शुरू हुआ, जिसमें सिग्नल स्टेशन पर एक ब्रीफिंग, पोर्ट बेसिन में वेसल टूर, और डीपी वर्ल्ड और पीएसए द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले दो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का साइट विज़िट शामिल था, जिसके बाद चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में एक इंटरेक्शन सेशन हुआ। फॉर्मल सेशन की अध्यक्षता चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन, आईएएस एस. विश्वनाथन ने की, और को-चेयर हैम्बर्ग पोर्ट अथॉरिटी के सीईओ और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ पोर्ट्स एंड हार्बर्स (आईएपीएच) के प्रेसिडेंट जेन्स मायर ने की। डॉ. एनारसु करुनेसन, रीजनल डायरेक्टर - साउथ एशिया, आईएपीएच मुख्य भाषण और प्रेजेंटेशन, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी पर एक प्रेजेंटेशन, पोर्ट और सीएसआर फिल्म की स्क्रीनिंग, और जेन्स मायर द्वारा एक प्रेजेंटेशन।

चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने पोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर-रेडी और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें -एआई-इनेबल्ड पोर्ट सिस्टम और पायलट प्रोग्राम, जैसे प्लानिंग और ऑपरेशनल ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए डिजिटल ट्विन की बढ़ती भूमिका शामिल है, पर अपने विचार शेयर किए।

सिम्स अस्पताल ने भारत का पहला एकीकृत स्लीप इंस्टीट्यूट लॉन्च किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारत में नींद संबंधी देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, सिम्स अस्पताल ने एकीकृत नींद संस्थान का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला पूर्णतः समन्वित, बहुविषयक केंद्र है जो विशेष रूप से नींद स्वास्थ्य को समर्पित है। नींद चिकित्सा में पारंपरिक रूप से देखे जाने वाले खंडित दृष्टिकोण को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह संस्थान, एक संरचित ढांचे के तहत 10 विशिष्टताओं को एकीकृत करता है, जिसमें चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, निदान और सहायक सेवाओं को एक सहज, साक्ष्य-आधारित देखभाल मार्ग में शामिल किया गया है। एक समर्पित नींद बोर्ड और उन्नत नींद विश्लेषण तकनीकों के साथ, यह संस्थान सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए तंत्रिका संबंधी, मनोवैज्ञानिक और श्वसन संबंधी नींद विकारों का व्यापक और व्यक्तिगत उपचार प्रदान करता है।

इस संस्थान का उद्घाटन मुख्य अतिथि अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश ने किया, जिन्होंने तमिल फिल्म 'देयर' में मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म नवविवाहित जोड़े की उन चुनौतियों को दर्शाती है, जब पत्नी के खर्राटों से पति की नींद खराब हो जाती है। एसआरएम ग्रुप के चेयरमैन डॉ. रवि पचामुथु इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। स्लीप इंस्टीट्यूट नींद से संबंधित विकारों के लिए विशेष उपचार प्रदान करता है, जिनका संबंध नींद के दौरान होने वाली हृदय संबंधी समस्याओं और स्ट्रोक से है।

ईएनटी सर्जन, पल्मोनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, बैरिएट्रिक विशेषज्ञ, ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन और कंजर्वेटिव डेंटिस्टों की एक बहु-विषयक टीम, सर्वोत्तम मानकों का सख्ती से पालन करते हुए, व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करती है। प्रदान किए जाने वाले उपचारों में पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (पीएपी) थेरेपी - सीपीएपी, ऑटो पीएपी, बाईपीएपी और एंडोस्कोपिक, प्लाज्मा-आधारित और रेडियोफ्रीक्वेंसी (आरएफ) विधियों सहित उन्नत, न्यूनतम इनवेसिव तकनीकों का उपयोग करके सर्वोत्तम मानक कंजर्वेटिव समाधान शामिल हैं, जिन्हें सटीक, रक्तहीन और दर्द रहित होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

संस्थान के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए, डॉ. रवि पचामुथु ने कहा, हमें भारत में व्यापक नींद देखभाल के लिए समर्पित पहले बहुविषयक संस्थान का शुभारंभ करते हुए खुशी हो रही है। एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्लीप हेल्थ भारत में नींद संबंधी विकारों के निदान और उपचार के तरीके को फिर से परिभाषित करता है। स्लीप इंस्टीट्यूट के प्रमुख और ईएनटी विभाग के निदेशक एवं वरिष्ठ सलाहकार डॉ. कार्तिक मदेश रत्नवेलु ने कहा, नींद संबंधी विकारों से पीड़ित व्यक्तियों में अक्सर स्ट्रोक और रात में दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं होती हैं। वास्तव में, इन जानलेवा घटनाओं का सामना करने वाले कम से कम तीन-चौथाई रोगियों में नींद संबंधी विकार अंतर्निहित होते हैं।

अनावरण दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कोयम्बटूर में इसरो के पूर्व चेयरमैन और चंद्रयान प्रोजेक्ट डायरेक्टर मायिलसामी अन्नादुरई ने गुरुवार को कोयंबटूर कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गांधीपुरम सिग्नल पर चंद्रयान और रोवर मॉडल स्टैच्यू का अनावरण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर पवन कुमार और अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।

जीतो स्वयम्-वी कनेक्ट महिला बिज़नेस रेफरल ग्रुप की बैठक सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) के स्वयम-वी कनेक्ट महिला बिज़नेस रेफरल ग्रुप की बैठक बेंगलूरु नॉर्थ कार्यालय में आयोजित की गई। महिला विंग की चेयरपर्सन लक्ष्मी बाफना की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रेफरल हेड लीला पितलिया, रेफरल लीड मीनू जैन एवं रेफरल मंत्री संगीता जैन उपस्थित थीं। मुख्य सत्र में माइंडसेट कोच एवं हिप्नोथेरेपिस्ट संगीता जैन ने 'मन' विषय पर प्रेरक एवं गतिविधि आधारित प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि हमारा मन एक सुपरकंप्यूटर की तरह कार्य करता है और जागरूक सोच हमारे आत्मविश्वास, कार्यों एवं परिणामों को सकारात्मक दिशा दे सकती है। उन्होंने अवचेतन मन की शक्ति, कल्पना के महत्व तथा विचार से परिणाम तक की प्रक्रिया को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए उपस्थित महिला उद्यमियों को अपनी सोच को सशक्त बनाने का संदेश दिया। विभिन्न सदस्याओं ने अपने अपने व्यापार की प्रस्तुति दी। बैठक में सर्वश्रेष्ठ 30 सेकंड पिच हेतु संतोष कोठारी, सर्वाधिक व्यवसाय करने हेतु सिंपल जैन तथा सराहना पुरस्कार हेतु रंजना दोधिया को सम्मानित किया गया।

मारवाड़ काँठा समाज की बैठक में समाजहित में अनेक निर्णय लिए गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय मारवाड़ काँठा समाज (तेरापंथी परिवार)की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक बुधवार को गांधीनगर स्थित तेरापंथ भवन में समाज के अध्यक्ष गौतमचन्द मुथा की अध्यक्षता में हुई। सहमंत्री कमल गादिया ने गत बैठक की कार्यवाही का वाचन किया।बैठक में समाजहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा अनेक सुझाव, विचारों का आदान प्रदान हुआ। संगठन के अध्यक्ष गौतमचंद मुथा ने सभी का स्वागत किया।

किक्रेट प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर मारवाड़ काँठा समाज लीग के संयोजक भूपेंद्र रायसोनी ने सभी सहयोगियों, प्रायोजकों व खिलाड़ियों को उनके सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। संवैधानिक प्रक्रियाओं के दस्तावेज तैयार करने हेतु अंकेक्षक अशोक सुराणा एवं उपाध्यक्ष पवन चौपड़ा, बैंकिंग संबंधित प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए प्रणव पोखरना को धन्यवाद दिया। भूपेंद्र रायसोनी ने क्रिकेट लीग की रिपोर्ट पेश की।ङबैठक में आगामी 8 मार्च को कृतज्ञता अर्पण समारोह एवं संगठन की वेबसाइट लांचिंग का आयोजन मुनि डॉ पुलकित कुमारजी के सान्निध्य में गांधीनगर भवन में होना तय हुआ और संयोजक के रूप में कमल गादिया को जिम्मेदारी दी गई। आगामी 5 अप्रैल को विराट स्नेह मिलन आयोजित करने के लिए भूपेंद्र रायसोनी को संयोजक बनाया गया। इस बैठक में 41 सदस्य उपस्थित थे। उपाध्यक्ष विनोद छाजेड़ ने धन्यवाद दिया। मंत्री नवनीत मुथा ने संचालन किया

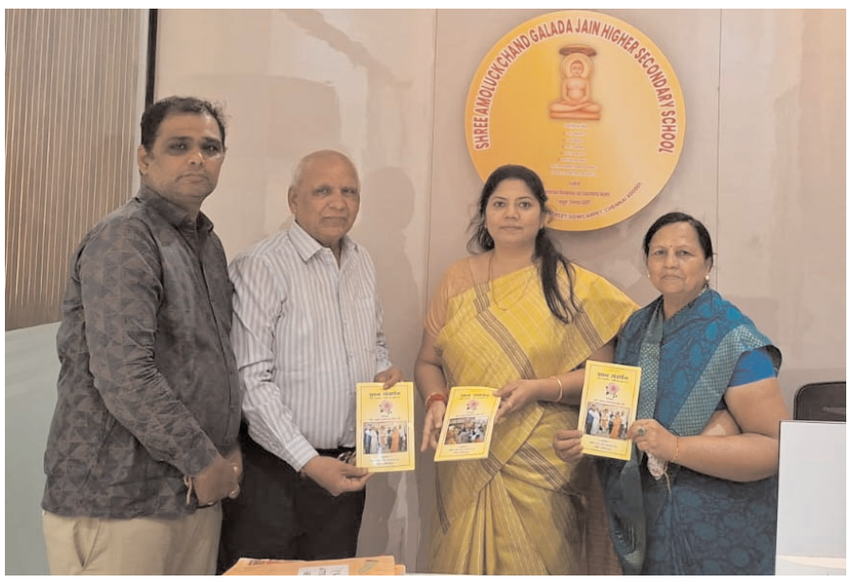

ज्ञान संवर्धन पुस्तकें भेंट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ के अध्यक्ष लाभचंद खारीवाल और मंत्री विजया कोटेचा ने 19 फरवरी को साहुकारपेट स्थित अमोलकचंद गेलड़ा विद्यालय के लिए विद्यालय की प्राचार्य जयश्री को 'ज्ञान संवर्धन' पुस्तकें भेंट की। विजया कोटेचा ने कहा कि शिक्षा के साथ ज्ञान भी जरूरी है। विद्यालय में संचालित नैतिक व आध्यात्मिक विकास कक्षाओं के लिए कार्यक्रम में ये पुस्तकें विद्यार्थियों को भी वितरित की गई। मार्गदर्शक कमला एस. मेहता के संपादन में स्वाध्याय संघ द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में बालकोपयोगी आध्यात्मिक सामग्री दी गई है। प्राचार्य जयश्री ने विजया कोटेचा का अभार जताया कि वे वर्षों से इस विद्यालय में नैतिक शिक्षण प्रदान कर रही हैं। अध्यक्ष लाभचंद खरीवाल ने विद्यालय में शिविर लगाने की बात कही। तरुण खारीवाल ने आभार जताया।

जीतो अपेक्स चेयरमैन ने हुब्बल्ली गर्ल्स हॉस्टल और एजुकेशन सेंटर का किया दौरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुब्बल्ली। शहर में जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) हुब्बल्ली के तत्वावधान में बन रहे गर्ल्स हॉस्टल और एज्यूकेशन सेंटर का गुरुवार को जीतो अपेक्स के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी ने दौरा किया और निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान अपेक्स चेयरमैन ने हुब्बल्ली के पदाधिकारियों से जीतो हॉस्टल के विकास, निर्माण व विद्यार्थियों के लिए तैयार की जा रही सुविधाओं व वातावरण के विषय में चर्चा की। उन्होंने जीतो हुब्बल्ली के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हॉस्टल निर्माण जीतो की समाज के प्रति शिक्षा व सेवा की प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस मौके पर गर्ल्स हॉस्टल और एजुकेशन सेंटर के चेयरमैन भरवरलाल जैन, जीतो चेयरमैन अनिल कुमार जैन, महासचिव प्रवीण चौधरी, सहचेयरमैन शरद मोमाया, जीतो इंटरनेशनल के पूर्व चेयरमैन गौतम ओसवाल, कांतिलाल शाह, रेखा शाह, राजन जैन, आशीष नाहटा, सज्जन पोरवाल आदि अनेक सदस्य उपस्थित थे।

महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव के लिए 'जेवाईएस' ने मंत्री को दिया न्यौता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन युवा संगठन (जेवाईएस) के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के योजना एवं सांख्यिकी मंत्री डी. सुधाकर से सौजन्य भेंट कर उन्हें 11 मार्च को आयोजित भगवान आदिनाथ के जन्म-दीक्षा कल्याणक तथा 31 मार्च को आयोजित भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव में अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मंत्री सुधाकर ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले ऐसे प्रेरणादायी आयोजनों को अपना समर्थन देने की भावना भी व्यक्त की। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष मुकेश सुराणा ने मंत्री को संगठन के उद्देश्यों तथा विगत कई दशकों से निरंतर संचालित सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर संगठन के मंत्री सुश्रुत चेलावत, जैन समन्वय समिति के चेयरमैन अनुराग ललवानी, सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी धर्मीचंद बोहरा, सज्जनराज मेहता एवं दिनेश खिंवेसरा आदि उपस्थित थे।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.